08
अध्याय

आर्थिक घटनाक्रम की समीक्षा

आर्थिक समीक्षा, 2015-16 ने वर्ष 2016-17 में जीडीपी में 7-7.5 प्रतिशत की दर से संवृद्धि का पूर्वानुमान लगाया था। अर्थव्यवस्था वास्तव में इसी पथ का अनुसरण कर रही थी और CSO के अनुमानों के अनुसार वर्ष के पूर्वार्द्ध में संवृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रही भी। किन्तु नवंबर में उठाए गए रू. 500 और रू. 1000 के नोटों के विमुद्रीकरण के क्रांतिकारी कदम के प्रभाव स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि में कुछ शिथिलता अपेक्षित है। यह CSO के प्रारंभिक अनुमान से कुछ धीमी दर पर ही संवृद्धि कर पाएगी। जनवरी 2017 के प्रारंभ में जो प्रारंभिक अनुमान जारी किए गए थे, वे तो विमुद्रीकरण से पहले की जानकारी, अर्थात वित्त वर्ष के शुरू के 7-8 महीनों की जानकारी पर आधारित थे और वे उसी अवधि की आर्थिक दशाओं को अभिव्यक्त कर पाते हैं। किन्तु भारत की संवृद्धि दर में कटौति के अनुमान तो 1/4 से 1/2 प्रतिशत अंक के ही है। यह भी संवृद्धि के मूल अनुमान को वैश्विक अर्थव्यवस्था की दुर्बलता और अस्थिरता (जहां 2016 में केवल 3 प्रतिशत की संवृद्धि हुई थी) के परिवेश में भारत की 7 प्रतिशत के निकट की संवृद्धि दर को बहुत ही महत्वपूर्ण स्वरूप प्रदान कर देती है। यही नहीं, यह उच्च संवृद्धि दर की प्राप्ति कई अन्य बड़ी बातों के साथ-साथ संभव हुई है : विमुद्रीकरण हुआ, विश्व भर में मंदी जैसा वातावरण रहा, अपेक्षाकृत निम्न स्फीति दर का समष्टि परिदृश्य रहा (पिछली सभी उच्च संवृद्धि घटनाएं तो उच्च स्फीति के साथ जुड़ी रही हैं), चालू खाते पर घाटा भी सामान्य स्तर पर रहा और डालर से रूपए की विनिमय दर भी स्थिर प्रायः रही है। अर्थव्यवस्था अपने राजकोषीय परिदृश्य को भी सुदृढ़ बना रही है। इन सबके बावजूद उच्च संवृद्धि दर का होना वास्तव में प्रशंसनीय है। सितंबर 2016 के अंत में सभी विदेशी ऋण सूचकों में भी सुधार ही दिखाई दे रहे थे ।

किन्तु अभी चुनौतियां भी विद्यमान हैं। निवेश जीडीपी अनुपात न केवल वांछनीय से निम्न स्तर पर है बल्कि इसमें पिछले कई वर्षों से निरंतर कमी आ रही है। तीव्र आर्थिक संवृद्धि को चिर स्थायी बनाने के लिए इस प्रक्रिया को शीघ्र ही परिवर्तित करना होगा। इसी प्रकार बचत की दर बढ़ानी होगी, ताकि बिना अधिक बाहरी वित्त के ही निवेश की दर में वृद्धि संभव हो सके। पिछले दो वर्षों तक स्थिरता के बाद विश्व में तेल कीमतें फिर ऊपर उठने लगी हैं। ये कोयले जैसी और चीजों के दामों में वृद्धि के साथ मिलकर स्फीतिकारी रूप धारण कर सकती हैं, इनसे व्यापार और राजकोषीय संतुलन पर दुष्प्रभावों की आशंका भी हो सकती है। आगामी वित्त वर्ष में जैसे-जैसे मुद्रा का परिचलन सामान्य होगा और सरकार द्वारा महत्वपूर्ण सुधार कार्य बल पकड़ेंगे, संवृद्धि में सुधार के आसार भी पैदा होते जाएंगे ।

I. विषय प्रवेश

8.1 CSO के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में 2016-17 में जीडीपी ने 7.1 प्रतिशत की संवृद्धि दर दर्ज की है (वैसे आगे चल कर अपने नए अनुमानों में CSO द्वारा इस संवृद्धि अनुमान को कुछ कम किए जाने की आशा है)। वर्ष 2016-17 के उत्तरार्द्ध में संवृद्धि दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान अक्टूबर 2016 तक (किसी-किसी मामले में नवंबर तक भी) की जानकारी पर आधारित हैं। अत: ये मुख्य रूप से वर्ष के प्रारंभिक 7-8 महीनों की प्रवृत्तियां ही दिखा रहे हैं।

रेखाचित्र 1: सकल घरेलू उत्पाद (GDP) तथा सकल मूल्य वृद्धि (GVA) में स्थिर कीमतों पर संवृद्धि (प्रतिशत)

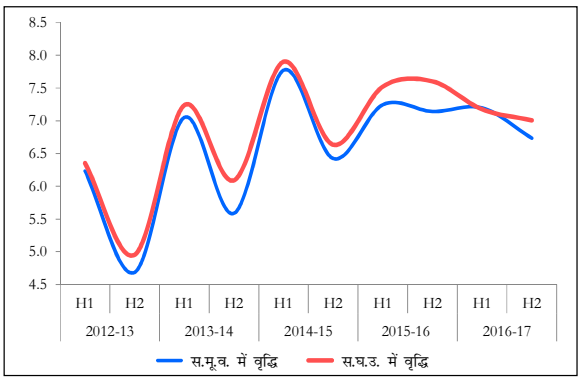

स्रोत : सीएसओ

8.2 प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार स्थिर कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि (GVA) 7 प्रतिशत है, जबकि 2015-16 में यह 7.2 प्रतिशत रही थी। वर्ष 2016-17 के उत्तरार्द्ध में यह संवृद्धि 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि पूर्वार्द्ध का अनुमान 7.2 प्रतिशत रहा है (रेखाचित्र 1)। क्षेत्रवार ब्यौरा तालिका-1 में दिया गया है।

8.3 आइए अब अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों पर विचार करें। वर्ष 2016-17 में कृषि और अनुषांगिक क्षेत्रों की संवृद्धि में बहुत सुधार हुआ है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि वर्ष 2014-15 और 2015-16 में मानसून पर्याप्त नहीं था, किन्तु इस वर्ष जलवृष्टि बहुत अच्छी रही है। अत: 2016-17 में कृषि में अच्छी संवृद्धि में आश्चर्य वाली कोई बात नहीं है। एक ओर खरीफ फसल के उत्पादन के प्रारंभिक अनुमान और दूसरी ओर रबी की अच्छी बुआई के आंकड़े इसी तथ्य की ओर इंगित कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र (जिसमें खनन, खान, विनिर्माण, विद्युत, गैस और जल आपूर्ति और निर्माण सम्मिलित हैं) ने 2015-16 में 7.4 प्रतिशत दर पर अच्छी संवृद्धि दर्ज की थी, किन्तु वर्तमान वर्ष में कुछ

तालिका 1 : GVA की संवृद्धि दर, विभिन्न क्षेत्रकों की आधार कीमतों के अनुसार (प्रतिशत)

क्षेत्र	2012-13[a]	2013-14[a]	2014-15[b]	2015-16[c]	2016-17[d]	2016-17	
						H1	H2
कृषि, वान्यिकी और मत्स्यन	1.5	4.2	-0.2	1.2	4.1	2.5	5.2
उद्योग	3.6	5.0	5.9	7.4	5.2	5.6	4.9
खनन-खदान	-0.5	3.0	10.8	7.4	-1.8	-0.9	-2.6
विनिर्माण	6.0	5.6	5.5	9.3	7.4	8.1	6.7
बिजली, गैस, जल आपूर्ति आदि	2.8	4.7	8.0	6.6	6.5	6.4	6.6
निर्माण	0.6	4.6	4.4	3.9	2.9	2.5	3.4
सेवा क्षेत्र	8.1	7.8	10.3	8.9	8.8	9.2	8.4
वाणिज्य, होटल, परिवहन, भंडारण	9.7	7.8	9.8	9.0	6.0	7.6	4.5
वित्तीय, भवन संपदा और व्यावसायिक सेवाएं	9.5	10.1	10.6	10.3	9.0	8.8	9.2
लोकप्रशासन, प्रतिरक्षा	4.1	4.5	10.7	6.6	12.8	12.4	13.2
आधारिक कीमतों पर ळट।	5.4	6.3	7.1	7.2	7.0	7.2	6.7

स्रोत: *सीएसओ*

नोट : a= दूसरा संशोधित अनुमान, b= पहला संशोधित अनुमान, c= अनंतिम अनुमान, d= पहला अग्रिम अनुमान

शिथिलता दर्शाई है। इसका मुख्य कारण पूंजीगत पदार्थ विनिर्माण और गैर स्थायी उपभोग पदार्थों के उत्पादन के औद्योगिक उत्पादन सूचक (IIP) में काफी कमी आना है। खान-खनन में तीखी गिरावट का कारण कच्चे तेल और गैस के उत्पादन में कमी हैं। किन्तु मूल्यवृद्धि के पटल पर औद्योगिक क्षेत्र निष्पादन IIP पर आधारित उपलब्धियों से बहुत भिन्न हैं। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी सेवा क्षेत्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था की संवृद्धि में योगदान देने वाला प्रधान क्षेत्र रहा है। लोक प्रशासन, प्रतिरक्षा और अन्य सेवाओं में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर एक बड़ा उछाल आया है। अत: 2016-17 में भी सेवा क्षेत्र की संवृद्धि दर 2015-16 के समान ही रहने की अपेक्षा है (तालिका-1)।

8.4 अचल/स्थिर निवेश (सकल स्थिर/अचल पूंजी निर्माण) का जीडीपी से अनुपात (चालू कीमतों पर) 2016-17 में 26.6 प्रतिशत रहने की आशा है। यह 2015-16 में 29.3 प्रतिशत था। किन्तु स्थिर कीमतों पर यह निवेश जीडीपी अनुपात 2015-16 के 3.9 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में ऋणात्मक (-)0.2 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2011-12 से ही अचल निवेश दर निरंतर कम हो रही है (रेखाचित्र 2) और मध्यम एवं दीर्घकालिक आर्थिक संवृद्धि के हितों का तकाजा है कि इस गिरावट की प्रवृति को शीघ्रतिशीघ्र उलटा जाए। निवेश और संवृद्धि को बढ़ावा देने के ध्येय से ही सरकार ने रिजर्व बैंक और अन्य पणधारियों के साथ मिलकर अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे व्यवसाय करने की सुविधा का उन्नयन हो और बैंकों तथा फर्मों के तुलनपत्रा में भी सुधार दिखाई दें।

8.5 वर्तमान वर्ष में जीडीपी संवृद्धि के मांग पक्ष का मुख्य उत्प्रेरक स्रोत सरकार के अंतिम उपभोग व्यय में 23.8 प्रतिशत की वृद्धि है (तालिका-2)। इस वर्ष में निजी उपभोग में भी अच्छी वृद्धि होने का पूर्वाकलन रहा है। स्वर्ण और चांदी के आयात में गिरावट यह संकेत दे रही है कि परिवारों द्वारा मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी में कमी होगी। वर्ष 2016-17 में आयात में कटौती निर्यात संकुचन की अपेक्षा अधिक गहरी रही है। इसी के कारण व्यापार घाटे में भारी गिरावट आई है। सेवा

रेखाचित्र 2 : जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल अचल पूंजी निर्माण (GFCF)

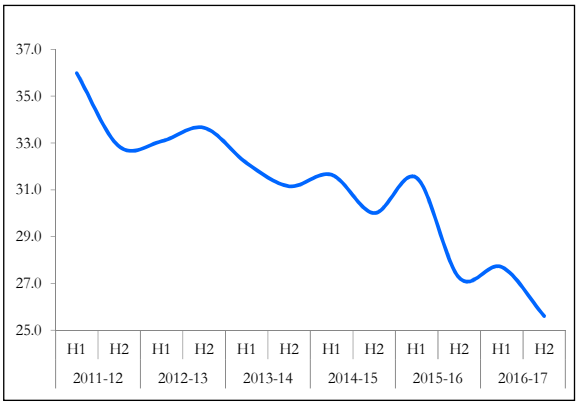

स्रोत: सीएसओ

तालिका 2: स्थिर कीमतों पर जीडीपी की संवृद्धि दर और उसके घटक

घटक	2012-13[a]	2013-14[a]	2014-15[b]	2015-16[c]	2016-17[d]	2016-17	
						H1	H2
सरकारी अंतिम उपभोग	0.5	0.4	12.8	2.2	23.8	16.9	32.4
निजी अंतिम उपभोग	5.3	6.8	6.2	7.4	6.5	7.1	6.0
सकल अचल पूंजी निर्माण	4.9	3.4	4.9	3.9	-0.2	-4.4	4.2
स्टॉक परिवर्तन	-3.8	-18.6	20.3	5.5	5.2	5.9	4.6
मूल्यवान पदार्थ	2.6	-42.2	15.4	0.3	-33.5	-47.9	-19.3
वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात	6.7	7.8	1.7	-5.2	2.2	1.7	2.6
वस्तुओं और सेवाओं के आयात	6.0	-8.2	0.8	-2.8	-3.8	-7.5	-0.1
जीडीपी	**5.6**	**6.6**	**7.2**	**7.6**	**7.1**	**7.2**	**7.0**

स्रोत: सीएसआर

नोट : a= दूसरा संशोधित अनुमान, b= पहला संशोधित अनुमान, c= अनंतिम अनुमान, d= पहला अग्रिम अनुमान

क्षेत्र के निर्यात में कुछ शिथिलता दिखी है, किन्तु वस्तु निर्यात के कारण व्यापार घाटे में कमी ने वस्तुओं और गैर-साधन सेवाओं के निवल निर्यात की (राष्ट्रीय आय लेखे में) स्थिति में सुधार किया है।

II. राजकोषीय घटनाक्रम

8.6 बजट 2016-17 ने सरकार की राजकोष व्यवस्था को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता को दोहराया है और राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष के 3.9 प्रतिशत से घटकर जीडीपी के 3.5 प्रतिशत के समान रह जाने का पूर्वानुमान है। इस सुदृढ़ीकरण की प्राप्ति के लिए सकल कर राजस्व में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि (2015-16 के अंतिम अनुमान की तुलना में) और गैर कर राजस्व तथा गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों में भारी वृद्धि की आशा की गई है। यह सब उस समय किया गया है जब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद सरकार की व्यय करने की विवशता में भारी वृद्धि हुई है।

8.7 केन्द्र सरकार की गैर ऋण प्राप्तियों (जिनमें निवल कर राजस्व, गैर कर राजस्व और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां सम्मिलित है) में अप्रैल-नवंबर 2016 में आया उत्प्लवन राजकोषीय शुचिता का समर्थक रहा है (तालिका 3)। अप्रैल-नवंबर 2016 में गैर ऋण प्राप्तियों में 25.8 प्रतिशत की वृद्धि तो पिछले वर्ष के अनंतिम प्राप्ति की वृद्धि के अनुमान से कहीं आगे निकल गई। गत वर्ष की तुलना में पूरे वर्ष में 16.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान बजट में लगाया गया था।

तालिका 3 : केन्द्र सरकार की गैर ऋण प्राप्तियां

	अप्रैल-नवंबर (ब.अ. के प्रतिशत के रूप में)		अप्रैल-नवंबर में वृद्धि (प्रतिशत)	
	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
सकल कर राजस्व	53.0	57.2	20.8	21.5
कर (केन्द्र को निवल)	50.5	58.9	12.5	33.6
कर-भिन्न राजस्व	78.1	54.2	34.9	1.0
ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां	25.8	48.5	180.3	57.1
कुल ऋण-भिन्न प्राप्तियां	53.9	57.4	20.0	25.8

स्रोत: सीजीए

नोट: बीई=बजट अनुमान

रेखाचित्र 3 : केन्द्रीय करों में वृद्धि (प्रतिशत)

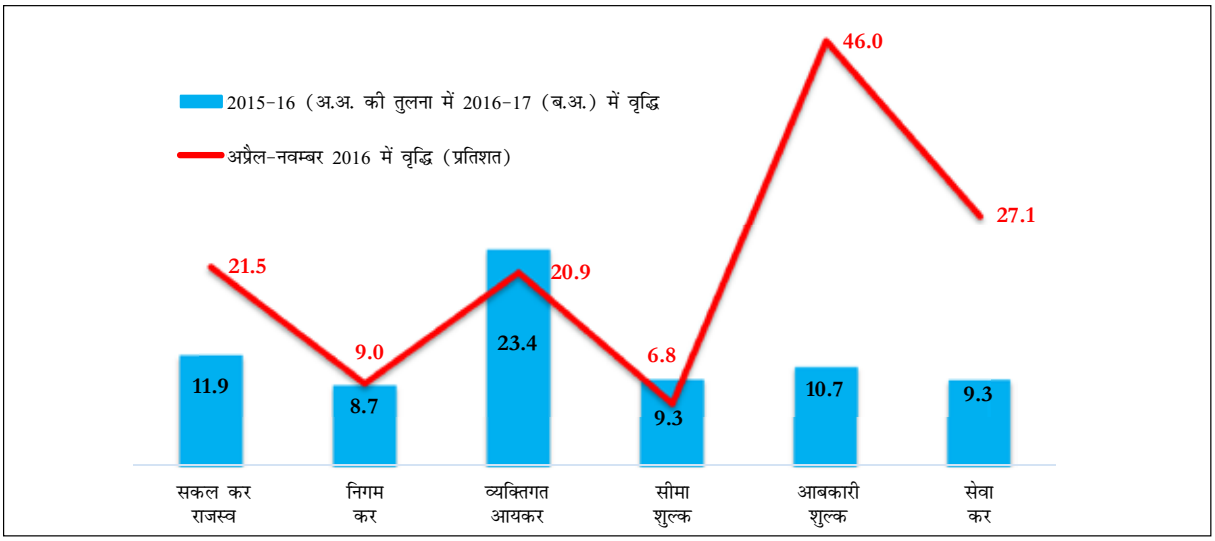

स्रोत: सीजीए

टिप्पणी: अ.व अनंतिम वास्तविक

8.8 कुल मिलाकर नवंबर 2016 तक कर संग्रह, विशेषकर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सेवाकर, में उत्प्लवन रहा है (रेखाचित्र 3)। उच्च मूल्य करेंसी नोटों की विधिग्राह्यता के समापन के अस्थायी दुष्प्रभाव के बाद भी नवंबर मास में अप्रत्यक्ष करों के राजस्व में 36.4 प्रतिशत का उछाल दिखाई दिया। अतिरिक्त कर प्रयासों द्वारा संसाधन जुटाने की नीति पर आचरण इस उत्प्लवन का आधार रहा है।

8.9 पिछले 5 वर्षों में सकल कर राजस्व का औसतन 34.5 प्रतिशत वर्ष की अंतिम तिमाही में ही एकत्र होता रहा है (वर्ष 2011-12 से 2015-16) इससे संकेत मिल रहे हैं कि इस वर्ष के बजट अनुमान प्राप्त करने में सफलता एक महत्वपूर्ण रूप में अंतिम तिमाही में आर्थिक गतिविधियों के स्तर और राजस्व संग्रह पर निर्भर रहेगी। इस तिमाही में आर्थिक गतिविधियों के स्तर पर उच्च मूल्य नोटों के विमुद्रीकरण तथा पुनः मुद्रीकरण के प्रति अर्थतंत्र की प्रतिक्रियाओं के प्रभाव अवश्य दिखाई देंगे।

8.10 अप्रैल-नवंबर 2016 में वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों के अंश के रूप में उगाहे गए सकल राजस्व का अनुपात पिछले वर्ष से कहीं अधिक रहा (तालिका 3)। राज्यों और संघशासित प्रदेशों को अन्तरण भी कर संग्रह के अनुरूप ही चला (रेखाचित्र 4)। कर अन्तरण, गैर योजना अनुदान और केंद्रीय सहायता के रूप में निवल संसाधान अन्तरण वर्ष भर के प्रस्तावित अनुमान के 58 प्रतिशत के समान रहा। यह पिछले वर्ष की तुलना में मामूली सा कम था।

8.11 अप्रैल-नवंबर 2016 में राजस्व खाते पर व्यय में देखने में बहुत वृद्धि हुई है (तालिका 4)। किन्तु इसे अन्य अनेक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में देखना अधिक उचित होगा। सबसे पहले तो राजस्व खाते पर व्यय में 'वेतन' मद का अंश सातवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आचरण के कारण बजट प्रावधान के अनुरूप ही 23.2 प्रतिशत अधिक हो गया। दूसरे वर्तमान वर्ष में प्रस्तावित मुख्य सब्सिडी मदों में 5.9 प्रतिशत की कटौति के स्थान पर अप्रैल-नवंबर 2016 में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (और वह भी पैट्रोलियम तथा उर्वरक सब्सिडी में गिरावट के बावजूद)। इसका मुख्य कारण खाद्य सब्सिडी में 21.6 प्रतिशत की वृद्धि है। यह इस वर्ष के आरंभ में अग्रिम के रूप में वितरित राशि है। और इसका प्रभाव वर्ष भर में धीरे-धीरे कम रह जाएगा। राजस्व व्यय में भारी वृद्धि का तीसरा कारण पूंजी परिसंपदा निर्माण हेतु अनुदान (GCCA) में इस अप्रैल-नवंबर 2016 की अवधि में 39.5 प्रतिशत की वृद्धि है। राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेशों को दिए गए सभी अनुदान, भले ही इनका एक अंश

रेखाचित्र 4 : अप्रैल-नवबंर में राज्यों और संघशासित क्षेत्रों को अंतरण

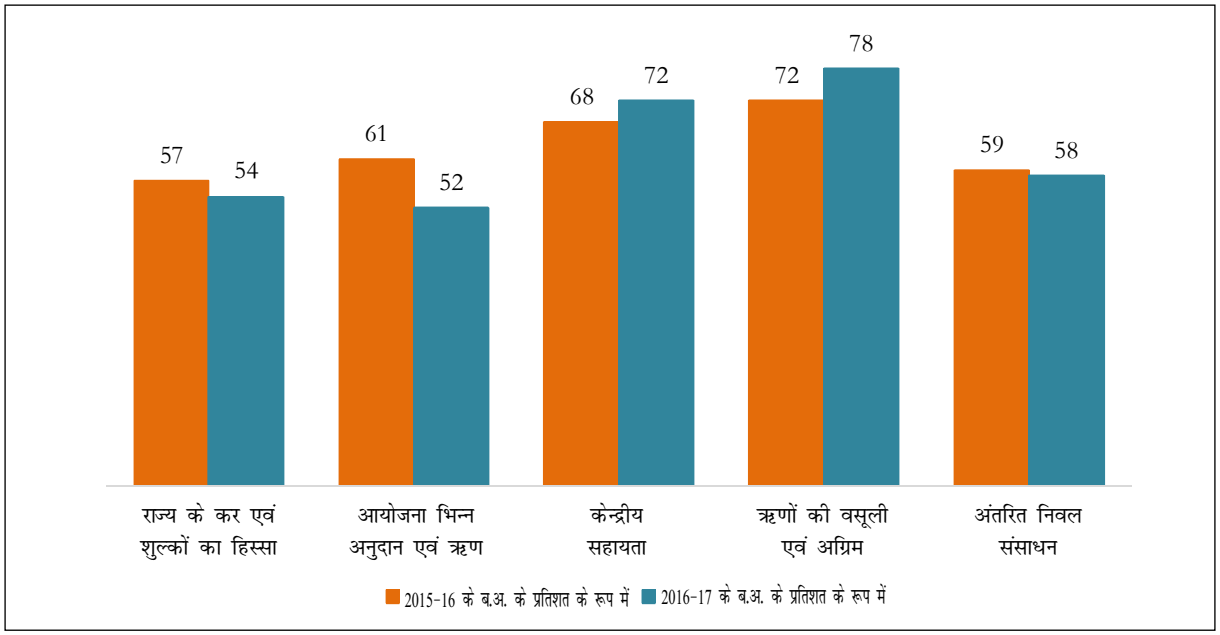

स्रोतः सीजीए

रेखाचित्र 5 : केन्द्र सरकार की बकाया देयताएं, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में

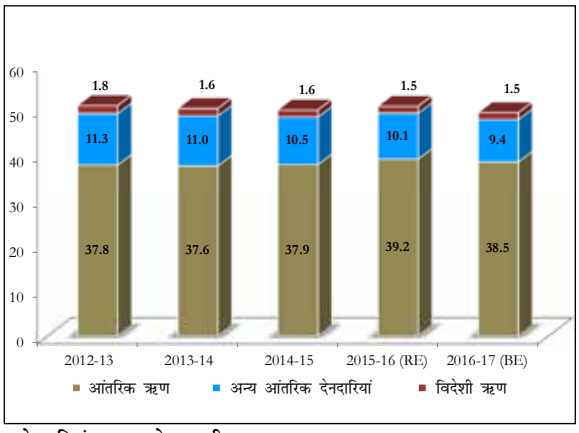

स्रोत: नियंत्रक महालेखा परीक्षक
टिप्पणी: RE-संसोधित अनुमान

पूंजी निर्माण के निमित्त हो, केन्द्र सरकार के राजस्व व्यय खाते में ही दिखाए जाते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण को दिए गए बढ़ावे का सही आकलन करना तो उक्त राशियों को राजस्व व्यय से घटाकर पूंजी व्यय में सम्मिलित करने पर ही संभव हो पाएगा। यह समंजन पूंजी एवं राजस्व व्ययों की संवृद्धि में विशाल खाई को भी कम कर सकता है।

8.12 केन्द्र सरकार की सकल वर्तमान देयताओं में सम्मिलित हैं : आंतरिक ऋण, भविष्य निधि और लघु बचतों में जमा राशियों जैसी अन्य आंतरिक देयताएं तथा बाह्य ऋण। वर्ष 2014-15 और 2015-16 में केन्द्र सरकार की सकल देयताओं में वृद्धि दरें समान प्राय: रही : क्रमश: 10.1 प्रतिशत और 10.4 प्रतिशत। किन्तु फिर भी केन्द्रीय सरकार के आंतरिक ऋण के जीडीपी से अनुपात में 2015-16 में वृद्धि हुई थी (रेखाचित्र 5)। इसका कारण ऋण वृद्धि क्रम में उछाल नहीं था, यह तो मौद्रिक जीडीपी की संवृद्धि में उस वर्ष में आयी कमी का प्रभाव था। ध्यान रहे कि उस वर्ष स्फीति दर में महत्वपूर्ण कमी के कारण वास्तविक जीडीपी की संवृद्धि तो अधिक उच्च दर पर रही थी। बजट में अनुमान लगाया गया है कि 2016-17 में सकल देयताएं पिछले वर्ष के 10.4 प्रतिशत से बहुत अधिक गिरकर मात्र 7.9 प्रतिशत रह जाएंगी।

III. कीमतें

8.13 लगातार तीसरे वर्ष उपभोक्ता कीमत सूचक (CPI) द्वारा मापित आधारिक स्फीति नियंत्रण में ही रही है। यह 2014-15 के 5.9 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 4.9 प्रतिशत रह गई थी। अप्रैल-दिसंबर 2016 में यह 4.8 प्रतिशत रही। वर्ष 2016-17 के प्रारंभिक महीनों में स्फीति दर में दालों और सब्जियों की कीमतों में वृद्धि के कारण कुछ सख्ती दिखाई दी थी, किन्तु दिसंबर 2016 में यह गिरकर अपने दो वर्षों के न्यूनतम स्तर 3.4 प्रतिशत तक पहुँच गई। यह कमी भी खाद्य कीमतों में गिरावट का परिणाम रही है (रेखाचित्र 6)।

8.14 थोक कीमत सूचक (WPI) के अनुसार स्फीति

तालिका 4 : केन्द्र सरकार के व्यय के मुख्य वर्ग

	अप्रैल-नवंबर ब.अ. के प्रतिशत के रूप में		अप्रैल-नवंबर वृद्धि (प्रतिशत)	
	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
कुल व्यय	64.3	65.0	6.3	12.6
राजस्व व्यय	64.0	66.1	3.2	16.4
ब्याज भुगतान	55.4	54.1	8.6	5.6
प्रमुख सब्सिडियां	82.9	85.3	-3.6	5.0
पेंशन	68.3	65.7	(-)1.4	34.1
वेतन	43.6	42.4	NA	23.2
पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान	73.2	67.7	-0.8	39.5
पूंजीगत व्यय	65.8	57.6	30.8	-10.4
समायोजित राजस्व व्यय	63.3	65.9	3.6	14.3
समायोजित पूंजीगत व्यय	68.1	61.7	18.1	6.4

स्रोत: महालेखा नियंत्रक
नोट :- समायोजित राजस्व और पूंजीगत व्यय का परिकलन राजस्व व्यय से पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाकर और इसे पूंजी व्यय में जोड़कर किया गया है।

दर 2015-16 में (-)2.5 प्रतिशत हो गई थी, जबकि 2014-15 में यह दर 2 प्रतिशत थी। यह गिरावट वर्तमान वर्ष में दो कारणों से विपरीत रूप धारण कर गई है। एक तो विश्व स्तर पर वस्तुओं की कीमतें ऊपर उठने लगी हैं और दूसरे तुलना का आधार बहुत कम (वास्तव में ऋणात्मक) है। IMF के कीमत सूचकों के अनुसार विश्व वस्तु और ऊर्जा कीमतों में 2016 के पहले 11 महीनों में क्रमशः 18 और 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। WPI स्फीति दर दिसंबर 2016 में 3.4 प्रतिशत थी (रेखाचित्र 7) और अप्रैल-दिसंबर 2016 में इसकी औसत दर 2.9 प्रतिशत रही।

8.15 भारत में बार-बार इनीगिनी खाद्य वस्तुओं के कारण स्फीति में तीखे उतार-चढ़ाव आ जाते हैं। दालें खाद्य स्फीति का मुख्य कारण बनी रही (रेखाचित्र 8ख। दालों, विशेषकर अरहर और उड़द की कीमतें मध्य 2015 से मध्य 2016 की अवधि में बहुत ऊंची रही। इसका मुख्य कारण आन्तरिक तथा वैश्विक आपूर्ति में कमी रहा है। जुलाई 2016 के बाद से चने की दाल को छोड़ शेष सभी दालों की कीमतें गिर रही हैं। इसके कारण है सामान्य प्रायः मानसून, रबी में दालों की अच्छी बुआई और सरकार द्वारा दालों के सुरक्षित भंडार की रचना। चीनी के दाम भी कम उत्पादन और विश्व चीनी बाजार

रखाचित्र 6 : उपभोक्ता कीमत सूचक (CPI) में आधार प्रभाव और कीमत प्रभाव प्रतिशत बिन्दुओं में)

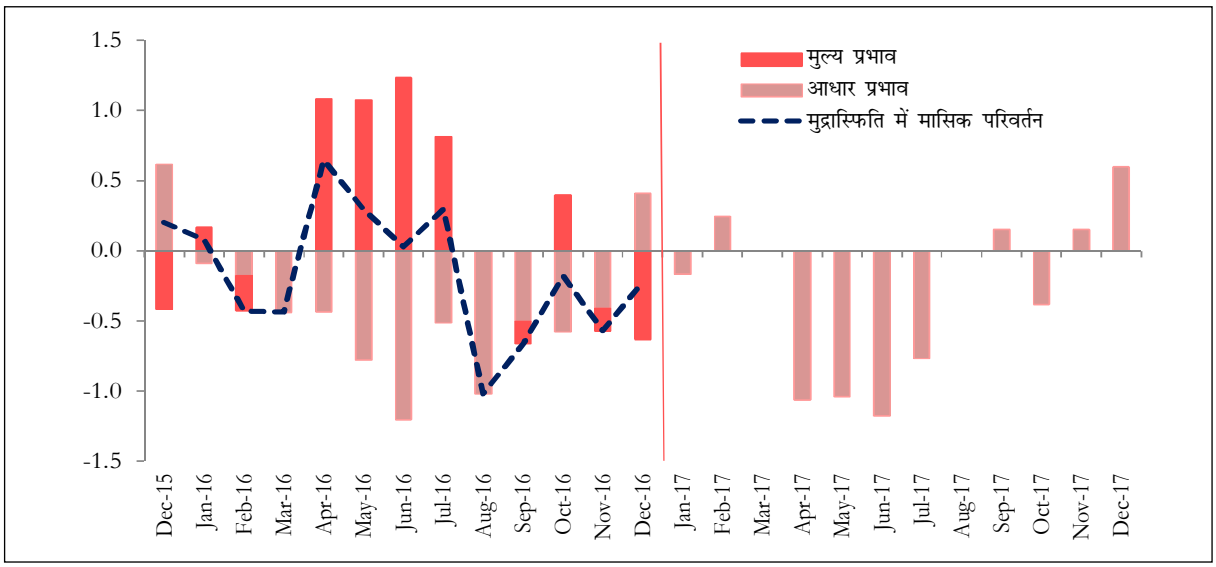

स्रोत: सीपीआई और सीएसओ के आंकड़ों को प्रयोग करने के बाद परिकलित

रेखाचित्र 7: WPI तथा CPI पर संयुक्त रूप से आधारित स्फीति दर (प्रतिशत)

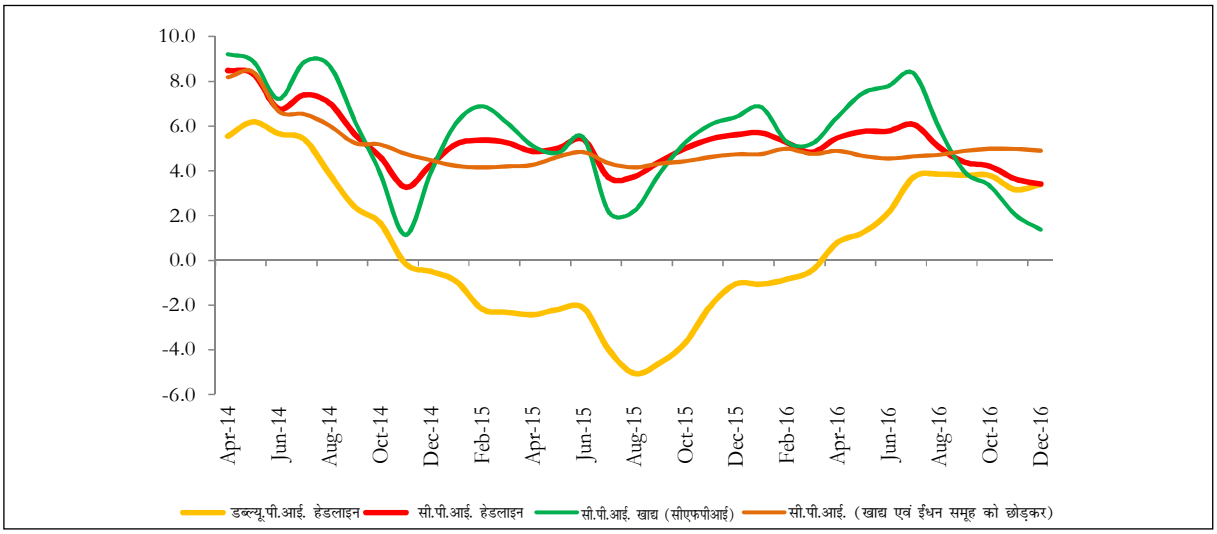

स्रोत: सीएसओ एवं डीआईपीपी

में दृढ़ता के कारण अधिक रहे हैं। सब्जियों के दाम गर्मियों में तो आसमान छू रहे थे, किन्तु मानसून के बाद और सर्दी की सब्जियों की आपूर्ति बाजार में पहुँचने पर इनकी कीमतों में तीखी गिरावट आई है। उपभोक्ता खाद्य स्फीति सूचक (CFPI) घटकर दिसंबर 2016 में दो वर्षों के न्यूनतम स्तर 1.4 प्रतिशत को छू गया है। दालों और उनके उत्पादों की स्फीति दर दिसंबर 2016 में (-)1.6 हो गई। सब्जियों की स्फीति दर तो सितंबर 2016 से ही ऋणात्मक चल रही है।

आधारभूत स्फीति अचल है

8.16 कुछ महीनों से तुलनात्मक आधार पर स्फीति दर में तीखी गिरावट आंकलित हो रही है किन्तु खाद्य एवं ईंधन समूह को छोड़कर CPI आधारित मूल स्फीति वर्तमान वित्तवर्ष में अभी तक तो अचल रही है (तालिका 5)। CPI आधारित परिष्कृत मूल स्फीति (खाद्य एवं ईंधन समूह पैट्रोल, डीजल को छोड़कर) वर्तमान वित्त वर्ष में अभी तक 5 प्रतिशत की औसत दर पर जमी हुई है। पान, तंबाकू, नशीले पदार्थ, परिधान, जूते आदि तथा आवास एवं शिक्षा समूहों की स्फीति भी अभी 5 प्रतिशत से अधिक है। और ये सभी आधारभूत स्फीति में एक बड़ा योगदान दे रहे हैं। परिवहन एवं संचार समूह में स्फीति दर विश्व तेल कीमतों में उछाल और उसकी आन्तरिक पैट्रोल-डीजल कीमतों में प्रतिध्वनि के कारण वृद्धिशील है। भारतीय खरीद वाले कच्चे तेलों के समुच्चय की कीमत अप्रैल 2016 में $39.9 से बढ़कर दिसंबर 2016 में $52.7 प्रति बैरल हो चुकी है। इसी प्रकार विश्व बाजार में सोने की उच्च कीमत का भी आधारभूत स्फीति दर की अचलता में योगदान रहा है।

स्फीति कुछ अपेक्षाएं

8.17 वर्तमान वित्तवर्ष के उत्तरार्द्ध में अभी तक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों की थोक और खुदरा कीमतें शिथिल पड़ती रही हैं। अत: CPI स्फीति दर के 5 प्रतिशत से कम हो जाने की आशा है। अगले वित्त वर्ष में वैश्विक वस्तु कीमतों, विशेषकर कच्चे तेल, में उछाल एवं स्फीति वृद्धि की आशंका को जन्म दे रहा है। हां रबी में अच्छी बुआई और दालों एवं मुख्य कृषि उत्पादों के वैश्विक उत्पादन में सुधार तथा सरकार द्वारा बेहतर खाद्य प्रबंधन और कीमतों की निगरानी के आधार पर खाद्य पदार्थों में स्फीति पर अंकुश रहने की आशा है।

IV. मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थी

8.18 वर्तमान वित्त वर्ष में सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन किया। इस संशोधन के अनुसार स्फीति के लक्ष्य सरकार निर्धारित करेगी, किन्तु यह कार्य रिजर्व बैंक से परामर्श करने के बाद पांच वर्ष में एक बार किया जाएगा। साथ ही एक अधिकार प्राप्त मौद्रिक नीति समिति (MPC) के गठन का भी प्रावधान किया गया है। नए मौद्रिक नीति परिवेश में

तालिका 5 : WPI और CPI में मापित त्रैमासिक स्फीति (प्रतिशत में)

	भारांश	2015-16				2016-17		
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3 (P)
डब्ल्यूपीआई आधारिक	**100.0**	**-2.3**	**-4.6**	**-2.3**	**-0.8**	**1.4**	**3.8**	**3.4**
सीपीआई आधारिक	**100.0**	**5.1**	**3.9**	**5.3**	**5.3**	**5.7**	**5.2**	**3.7**
I. खाद्य एवं पेय पदार्थ	45.9	5.4	3.3	5.9	5.8	7.0	6.0	2.8
II. पान, तम्बाकू आदि	2.4	9.5	9.5	9.4	8.7	7.7	6.8	6.6
III. परिधान एवं पदगाण	6.5	6.1	5.9	5.7	5.6	5.3	5.2	5.0
IV. आवास	10.1	4.6	4.6	5.0	5.3	5.4	5.3	5.1
V. ईंधन और प्रकाश	6.8	5.8	5.5	5.3	4.5	3.0	2.8	3.2
VI. विविध	28.3	3.8	3.3	3.7	4.1	4.0	4.2	4.7
सीएफपीआई*	39.1	5.1	2.7	5.9	5.8	7.2	6.1	2.2
खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई	47.3	4.6	4.3	4.6	4.8	4.7	4.7	5.0

स्रोत: **डीआईपीपी, कें.सां.का.**

नोट: **P: अनंतिम *सीएफपीआई: उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक**

रेखाचित्र 8 : CPI आधारिक, खाद्य एवं आधार स्फीति के प्रचालक
(प्रतिशत बिन्दु योगदान)

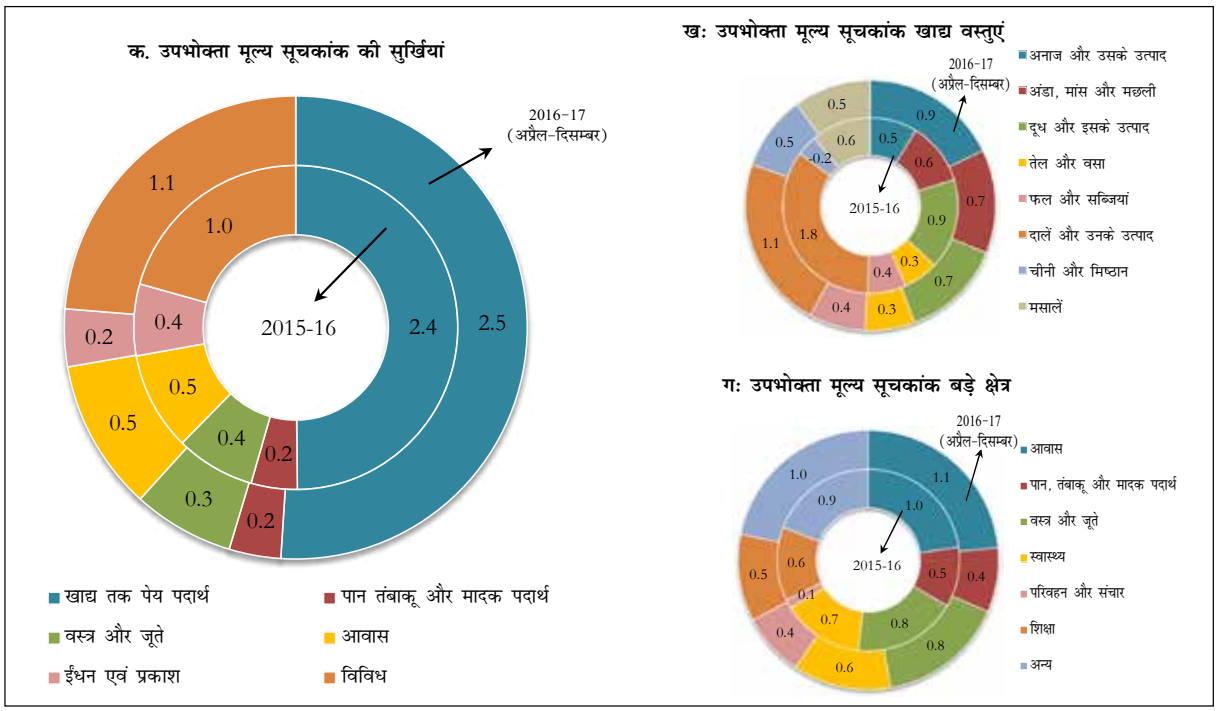

स्रोत: **सीपीआई और सीएसओ के आंकड़ों के आधार पर परिकलित**

सरकार ने स्फीति का लक्ष्य 4 प्रतिशत रखा है। इसमें ऋणात्मक/धनात्मक 2 प्रतिशत अंकों का उतार चढ़ाव स्वीकार्य घोषित किया गया है, अवधि 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 तक रहेगी। सरकार ने सितंबर 29, 2016 को MPC का गठन भी अधिसूचित कर दिया है। अभी तक MPC की दो बैठकें हो चुकी हैं। पिछली बैठक दिसंबर 7, 2016 को हुई थी, उसने सुविधाकारी मौद्रिक नीति परिप्रेक्ष्य को बनाए रखा है किन्तु नीति आधारित दरों में कोई परिवर्तन नहीं किए। अक्टूबर 4, 2016 की पहली बैठक ने नीति दर को 0.25 प्रतिशत घटाकर 6.25 कर दिया था। अत: तरलता समंजन सुविधा (LAF) के अंतर्गत विपरीत रेपो दर 5.75 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर 6.75 प्रतिशत बनी हुई है।

8.19 रिजर्व बैंक ने भी अप्रैल 2016 में अपनी मौद्रिक नीति की रूपरेखा को और परिष्कृत किया है। इसके लक्ष्य नियमित सुविधाओं के माध्यम से तरलता की अल्पकालिक जरूरतें पूरी करना (घर्षणीय और मौसमी असंतुलन दूर करने के लिए नीतियों में सूक्ष्म स्तरीय फेरबदल करना और इसके तुलनपत्र में निवल विदेशी एवं निवल आंतरिक परिसंपदा के बीच संतुलन लाकर तरलता में अधिक स्थायी रूप से सुधार करना था। अभी तक MPC अपने लिए निश्चित कार्यविधि का ही पालन कर रही है।

तरलता की अवस्था

8.20 रिजर्व बैंक अपनी तरलता प्रबंधन रूपरेखा के अनुसार ही कार्य कर रहा है (रेखाचित्र 9)। इसने प्रारंभिक तरलता की स्थितियों को निष्पक्षता के निकट लाने के लिए खुले बाजार की प्रक्रियाओं (OMOs) के माध्यम से स्थायी तरलता का प्रसार किया है। पूर्वनिर्दिष्ट नोटों की वापसी के बाद रिजर्व बैंक ने अभूतपूर्व कदम उठाकर बाजार से परिवर्ती विपरीत रेपो दर के माध्यम से तरलता को सोखने का काम किया है। रिजर्व बैंक के कार्य में सहयोग देते हुए इसकी बाजार स्थायित्वकरण निक्षेप सीमा को रू. 30,000 करोड़ से बढ़ाकर रू. 6 लाख करोड़ कर दिया है। वर्ष 2016-17 की प्रारंभिक तिमाही में तरलता की दशा में काफी कसाव था। आगे

के महीनों में एक दो घटनाओं को छोड़ इसमें बहुत नम्यता आई है। भारित औसत अविलम्ब राशि (WACR) नीति दर की उच्च एवं निम्न सीमाओं के बीच उनका उल्लंघन किए बिना ही मंडराती रही है।

8.21 अप्रैल 2016 में रेपोदर में 25 आधरिक बिन्दुओं की कटौती के बाद 91 दिनों की राजकोषीय हुन्डियों पर प्रति प्राप्ति दर में तीखी गिरावट दिखाई दी थी। किन्तु 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर इस दर की कटौति का कोई विपरीत प्रभाव नहीं दिखाई पड़ा। वास्तव में इन पर प्रतिप्राप्तियों में हल्का सा सुधार ही हुआ था (रेखाचित्र 10)। हां, इन प्रतिभूतियों पर दर में जून 2016 के बाद कुछ नरमी आना शुरू हो गई है। दिसंबर 30, 2016 के दिन 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रति प्राप्ति दर 6.63 प्रतिशत आंकी गई है।

8.22 किन्तु दरों में कटौति का आगे की ओर प्रसार पूरी तरह से नहीं हो पाया है। आधारिक उधार दर अप्रैल 2016 के 9.30/9.70 से घटकर दिसंबर 30, 2016 तक 9.30/9.65 ही हो पायी है। वस्तुत: एक वर्ष से अधिक की सावधी जमाओं पर ब्याज दर इसी अवधि में 7.00/7.50 प्रतिशत से घटकर 6.50/7.00 रह गई हैं।

बैंक क्षेत्रक

8.23 बैंक क्षेत्रक, विशेषकर सार्वजनिक बैंको, का निष्पादन वर्तमान वित्तवर्ष में फीका ही रहा है। बैंकों की परिसंपदा गुणवत्ता में और ह्रास हुआ है। सभी अनूसूचित व्यापारिक बैंकों का सकल निष्पादनहीन परिसंपदाओं का सकल उधार/साख से अनुपात मार्च से सितंबर, 2016 की अवधि में ही 7.8 प्रतिशत से बढ़कर 9.1 प्रतिशत हो गया। वर्षानुगत आधार पर कर पश्चात् लाभ (PAT) जोखिमों के प्रावधान, ऋण माफी और निवल ब्याज आय में कमी के कारण 2016-17 के पूर्वार्द्ध में संकुचन दर्शा रहा है।

साख/उधार की संवृद्धि

8.24 बकाया गैर खाद्य उधार (NFC) की वृद्धि सभी महीनों में 10 प्रतिशत से कम रही। केवल सितंबर 2016 ही अपवाद था (रेखाचित्र 11)। औद्योगिक क्षेत्र को साख वृद्धि की दर तो निरंतर 1 प्रतिशत से कम रही है, अगस्त और अक्टुबर में तो इसमें संकुचन भी हुआ है। बैंकों के कृषि एवं अनुषांगिक कार्यों, और व्यक्तिगत ऋण के वर्ग गैर-खाद्य साख में वृद्धि में मुख्य योगदान कर रहे हैं।

निगम बाँड बाजार को सुदृढ़ करने के उपाय

8.25 भारत के निगम क्षेत्र के बाँडों के बाजार को

रेखाचित्र 9 : तरलता की अवस्था (हजार करोड़ रूपयों में)

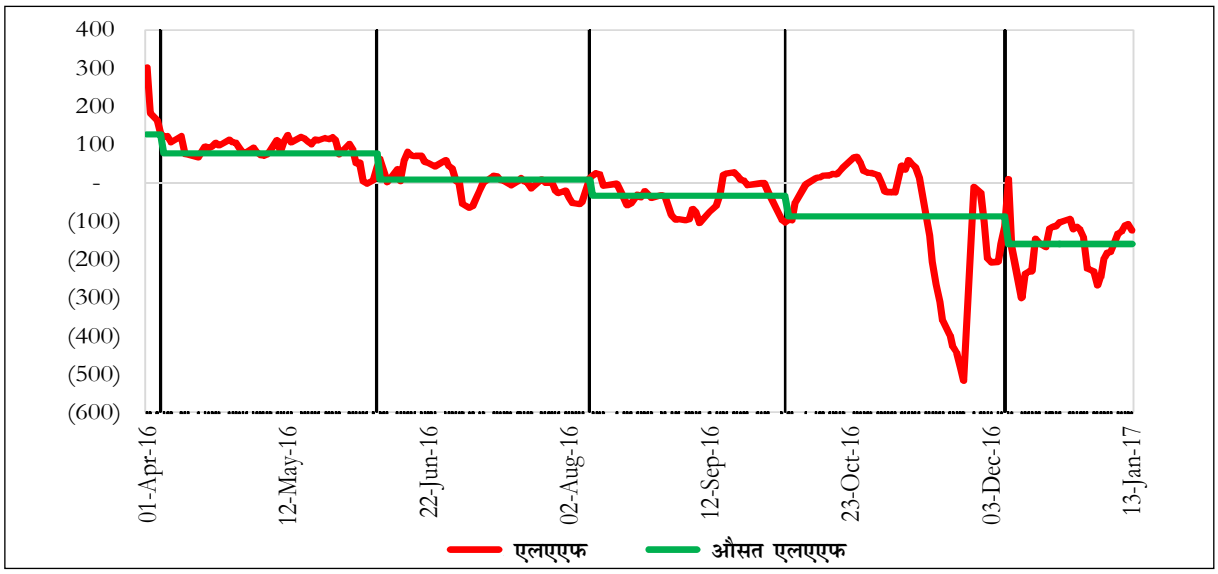

स्रोत: आर.बी.आई.

रेखाचित्र 10 : मुख्य दरों के उतार-चढ़ाव (प्रतिशत)

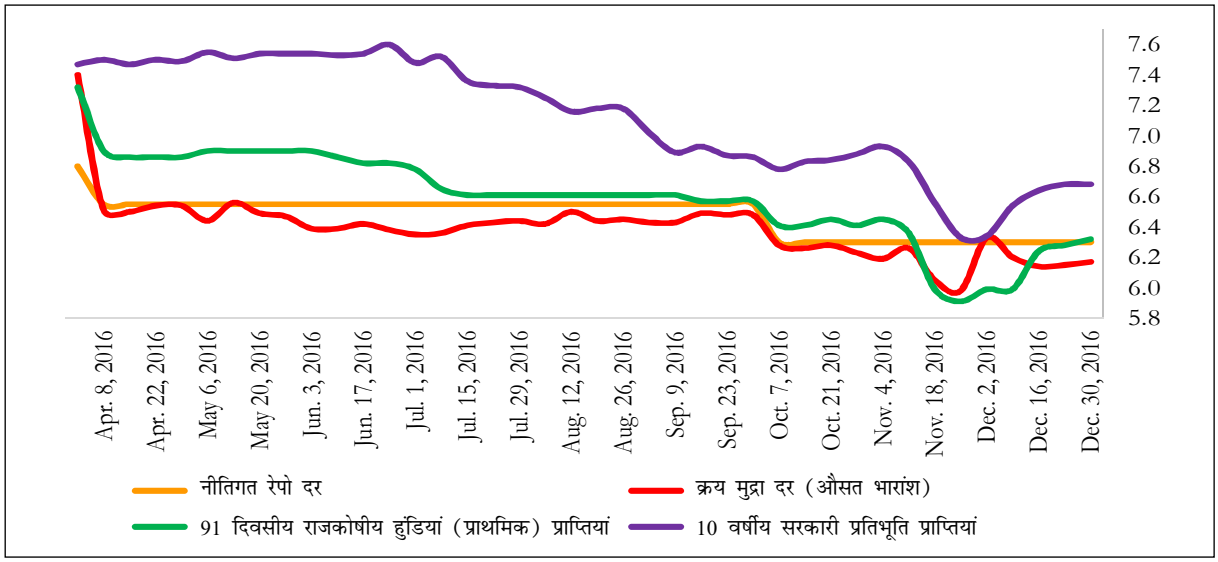

स्रोत: आर.बी.आई.

सुदृढ़ करने के लिए रिजर्व बैंक ने अनेक कदम उठाए हैं। इन बांडों के बाजार में तरलता बढ़ाने और निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इसने खान समिति की अनेक सिफारिशों को स्वीकार किया है। रिजर्व बैंक द्वारा घोषित नए कदम इस प्रकार हैं : (क) व्यापारिक बैंक अपनी पूंजीगत जरूरतों तथा संरचना वित्तीयन एवं सस्ते आवास खंडों के वित्तीयन के लिए विदेशों में रूपयों में मान्य बाँड (मसाला बाँड) जारी कर सकते हैं; (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पास पंजीकृत वे दलाल जो निगम बाँड बाजार में कार्य करने हेतु अनुमोदित हैं, निगम ऋण पत्रों की रेपो और विपरीत रेपो संविदाएं भी स्वीकार कर सकते हैं। इससे निगम बाँड चिरभोग्य स्वरूप धारण कर लेंगे और इनके द्वितीयक बाजार में लेनदेन में वृद्धि होगी; (ग) बैंक निगम बाँड निर्गम हेतु 20 प्रतिशत नहीं 50 प्रतिशत अग्रिम साख प्रदान कर सकते हैं। यह अपेक्षाकृत निम्न गुण निगम बाँडों को भी बाजार तक पहुँचने में सहायक कदम होगा; (घ) प्राथमिक विक्रेताओं को सरकारी बाँडों के

रेखाचित्र 11 : NFC और इसके घटकों में प्रतिशत वृद्धि

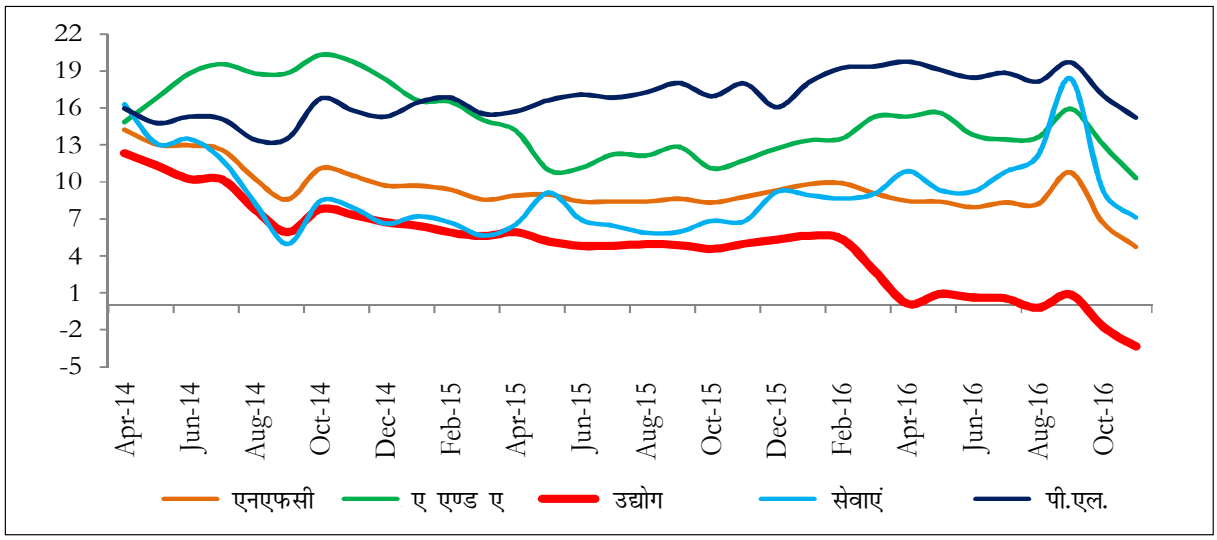

स्रोत: आर.बी.आई.

बाजार निर्माता के रूप में काम करने की अनुमति, यह सरकारी प्रतिभूतियों को खुदरा निवेशकों तक पहुँचाने में सहायक होगा; और (च) काऊंटर पर और एक्सचेंज में विक्रीय करेंसी व्युत्पन्न निक्षेपों की पूर्वोपायी कार्य के लिए विदेशी मुद्रा बाजार तक पहुँच सरल बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने विनिमय दर जोखिम के अधीन निकायों को अमेरीकी $30 मिलियन तक के पूर्वोपायी लेनदेन किसी भी समय कर लेने की छूट दी है।

भारतीय बाजारों का निष्पादन

8.26 वर्ष 2016 में भारतीय बाजारों के निष्पादन में सामान्य संवृद्धि दिखाई दी है। सेंसेक्स में यह 1.95 तथा निफ्टी में 3 प्रतिशत रही है (वर्ष 2015 में तो घाटा ही रहा था)।

8.27 भारतीय बाजारों में यह उत्थान क्रम सितंबर 2016 तक चला किन्तु बाद में शिथिल पड़ गया (रेखाचित्र 12)। इसका मुख्य कारण उदीप्यमान बाजारों से विदेशी पूंजी का पलायन रहा। वैश्विक और आन्तरिक कारकों के भारतीय पूंजी बाजार पर बड़े महती प्रभाव रहे। कुछ अधिक सतर्कतापूर्वक अवलोकित घटनाक्रमों में ब्रेक्जिट, अमेरीकी राष्ट्रपति चुनाव तथा अमेरिकी संघीय रिजर्व व्यवस्था और भारतीय रिजर्व बैंक की घोषणाएं रहीं। बाजार की भावनाओं को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में ओपेक द्वारा तेल उत्पादन विषयक नीति निर्णय भी रहे।

विदेशी पत्राक निवेश (FPI)

8.28 वर्ष 2008 में वित्तीय संकट के बाद पहली बार निवल विदेशी पत्रक निवेश ऋणात्मक हुआ है, अर्थात भारत के पूंजी बाजार से रू. 23079 करोड़ की राशियों का पलायन हुआ है (तालिका 6)। यह FPI पलायन केवल भारत से नहीं हुआ, विदेशी निवेशकों ने बड़े स्तर पर सभी उदीप्यमान बाजारों से अपनी पूंजी निकाली है, क्योंकि उन्नत देशों में उन्हें अधिक प्रति प्राप्ति दर की संभावनाएं दिखाई देने लगी हैं।

V. भारत का वस्तु व्यापार

निर्यात

8.29 वैश्विक संवृद्धि और व्यापार के साथ-साथ भारत के निर्यात में भी 2014-15 और 2015-16 में क्रमशः 1.3 प्रतिशत और 15.5 प्रतिशत की कमी हुई है। वर्ष 2016-17 में यह ऋणात्मक प्रवृत्ति कुछ बदली है। अप्रैल-दिसंबर 2016 में निर्यात में 0.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह 2015-16 के इन्हीं महीनों की तुलना में

रेखाचित्र 12 : भारतीय पूंजी बाजार के आधारभूत सूचक : सेनसेक्स और निफ्टी
(एक जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 की अवधि के दैनिक उच्चावचन)

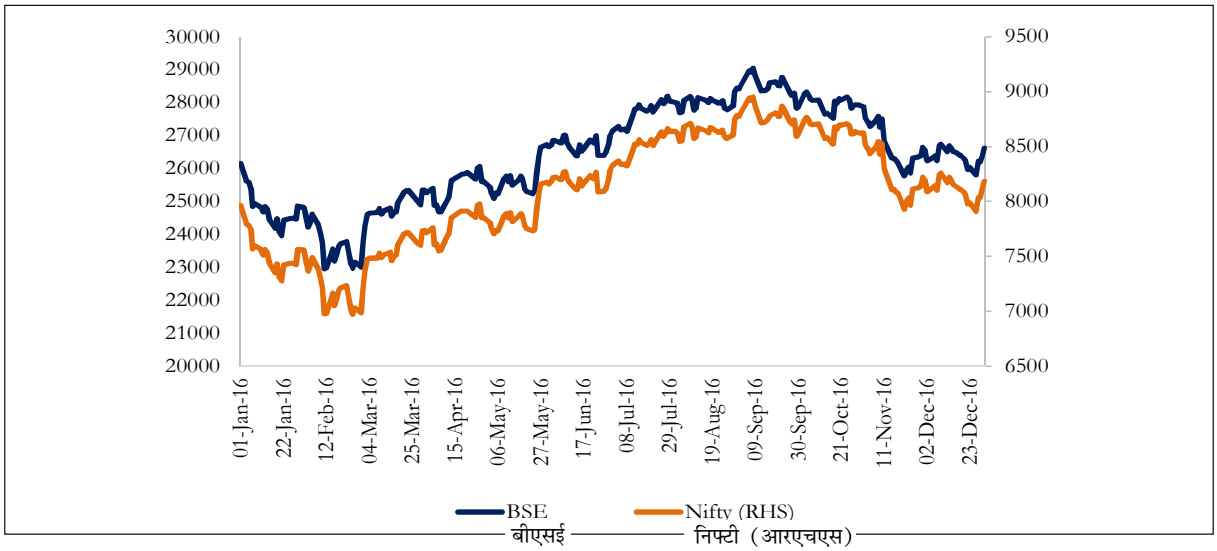

स्रोत: निफ्टी, सेन्सेक्स

$197.3 बिलियन से अधिक होकर $198.8 बिलियन हो गया। वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) में पैट्रोलियम तेल और तैलीय (POL) पदार्थ निर्यात (जो देश के कुल निर्यात के 11.1 प्रतिशत हैं) में 9.8 प्रतिशत की गिरावट होकर यह $22.0 बिलियन ही रह गए। गैर POL निर्यात में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उनके आंकड़े $176.8 बिलियन पर पहुँच गए। वर्ष 2015-16 की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2016 में बहुत से निर्यात क्षेत्रक पुनः धनात्मक संवृद्धि दिखाने लगे हैं (तालिका 7)।

8.30 भौगोलिक क्षेत्रनुसार विचार करें तो यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, सीआई एस और बाल्टिक देशों को भारत के निर्यात में 2015-16 में कमी आई थी। किन्तु अप्रैल-नवंबर 2016-17 में यूरोप, अमेरिका और एशिया का हमारे निर्यात क्रमशः 2.6, 2.4 और 1.1 प्रतिशत अधिक हुए हैं, जबकि अफ्रीका को निर्यात में 13.5 प्रतिशत की कमी रही है। भारत से निर्यात की लदाई संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब गणराज्य और हांगकांग के लिए इसी क्रम के अनुसार हुई है।

आयात

8.31 वर्ष 2014-15 के $448 बिलियन की तुलना में आयातों का मूल्य 2015-16 में घटकर $381 बिलियन रह गया था। इसका मुख्य कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट थी, उसके कारण POL आयात मूल्य में बड़ी भारी कमी आई थी। अप्रैल-दिसंबर 2016 में आयात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.4 प्रतिशत की और कमी होकर ये आंकड़े $275.4 बिलियन रह गए। POL आयात में तो 10.8 प्रतिशत की कमी आई थी। सोना और चांदी का आयात 35.9

तालिका 6: 2010-16 में भारत में निवल FPI/FII निवेश (करोड़ रूपयों में)

प्रकार	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
अंश पूंजी	133266	-2714.3	128360	113136	97054	17808	20568
ऋण पूंजी	46408	42067	34988	-50849	159156	45857	-43647
सकल	**179674**	**39352.9**	**163348**	**62286**	**256213**	**63663**	**-23079**

स्रोत: एनएसडीएल

तालिका 7 : कुल महत्वपूर्ण क्षेत्रों का निर्यात निष्पादन

	2015-16	2010 (अप्रैल-नवम्बर (P)
सकारात्मक संवृद्धि	रसायन एवं अनुषांगिक उत्पाद (0.6)	खनिज एवं अयस्क (35.3) सागरीय उत्पाद (20.6) जवाहरात और आभूषण (11.6) इलैक्ट्रॉनिक सामान (3.0) इंजिनियरी उत्पाद (0.9)
ऋणात्मक संवृद्धि	वस्त्र (-3.2) जवाहरात एवं आभूषण (-4.8) इलैक्ट्रॉनिक सामान (-5.3) चमड़ा (-10.3) सागरीय उत्पाद)-13.5) अयस्क एवं खनिज (-16.4) इंजिनियरी उत्पाद (-17.0) कृषि एवं अनुषांगिक उत्पाद (-17.6) पैट्रोलियम उत्पाद (-46.2)	रसायन एवं अनुषांगिक उत्पाद (-0.5) कृषि एवं अनुषांगिक उत्पाद (-3.0) चमड़ा (-4.8) वस्त्र (-5.2) पैट्रोलियम उत्पाद (-9.8)

स्रोत: वाणिज्य विभाग

नोट : कोष्टक के अंक वर्षानुगत संवृद्धि दर्शा रहे हैं।

P: **अनंतिम, त्वरित अनुमान निर्दिष्ट हैं।**

प्रतिशत कम हुआ। लेकिन गैर POL और गैर सोना चांदी आयात के मूल्य में केवल 2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। मोतियों एवं अर्द्ध कीमती रत्नों का आयात 19.0 प्रतिशत अधिक हुआ तो खाद्य एवं अनुषांगिक उत्पाद आयात में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पूंजीगत पदार्थों का आयात 8.8 प्रतिशत कम किया गया।

8.32 भारत के यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया तथा CIS-बाल्टिक क्षेत्रों से आयात में 2015-16 में कमी आई थी। किन्तु अप्रैल-नवंबर 2016 में CIS और बाल्टिक क्षेत्र से आयात में 10.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि अन्य चार क्षेत्रों से आयात में कमी ही हुई है। भारत के शीर्ष तीन आयात स्रोत क्रमशः चीन, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका रहे (अप्रैल-नवंबर, 2016)।

व्यापार घाटा

8.33 वर्ष 2015-16 में (पिछले वर्ष की तुलना में) व्यापार घाटा 13.8 प्रतिशत कम होकर $118.7 बिलियन रह गया था। यही नहीं यह 2015-16 की तुलनीय अवधि के $100.1 बिलियन की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2016 में मात्र $76.5 बिलियन ही रह गया था।

VI. भुगतान शेष

चालू खाता (CAD)

8.34 भारत के निर्यात में कुछ कमी के बावजूद देश के बाह्य क्षेत्र की स्थिति संतोषजनक रही है, चालू खाते का घाटा 2012-13 से निरंतर कम हो रहा है। उस वर्ष में यह जीडीपी के 4.8 प्रतिशत अर्थात $88.2 बिलियन स्तर पर था। यह 2015-16 में घटकर केवल $22.2 बिलियन रह गया (जीडीपी का 1.1 प्रतिशत)। वर्ष 2016-17 के पूर्वार्द्ध में यह CAD और घटकर जीडीपी का 0.3 प्रतिशत रह गया है। इस व्यापार घाटे की तीखी कमी निर्यात से प्राप्तियों में कमी को कहीं न कहीं छुपा लेती है। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में निरंतर कमी से तेल आयात बिल में 18 प्रतिशत कमी आई। साथ ही सोने के आयात में भारी गिरावट ने BoP आधार पर भारत के सकल आयात को बहुत घटा दिया। सेवा क्षेत्र की निवल प्राप्तियों में 2016-17 के पूर्वार्द्ध में 10 प्रतिशत की कमी रही। यद्यपि सेवा प्राप्तियां तो इस अवधि में 4 प्रतिशत अधिक थीं, किन्तु सेवाओं के लिए भुगतान में 16 प्रतिशत का उछाल आ गया था। फिर भी, सॉफ्टवेयर से प्राप्तियों में मामूली सुधार था और वित्तीय सेवाओं से प्राप्तियाँ तो कम ही हुई थीं। खाड़ी क्षेत्र के देशों में तेल कीमत में कमी के कारण आर्थिक वातावरण मंद था और उसके कारण वहां कार्य कर रहे भारतीय समुदाय द्वारा प्रेषित राशियां भी निरंतर कम हो रही थीं। ये निजी खाते के अंतरण 2015-16 के पूर्वार्द्ध के $32.7 बिलियन से कुछ घटकर 2016-17 के पूर्वार्द्ध में $28.2 बिलियन रह गए।

पूंजी/वित्त खाता

8.35 विदेशी ऋणों पर अधिक ब्याज, बैंकों द्वारा विदेशी करेंसी साधन एकत्र करने से उनकी निवल पूंजी में ह्रास, अनिवासी भारतीयों की निवल जमाओं में कमी के बावजूद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निवल विदेशी पत्रक निवेश के प्रबल प्रवाहों ने न केवल CAD का वित्तीय प्रबंधन कर दिया बल्कि 2016-17 के पूर्वार्द्ध में विदेशी पूंजी के सुरक्षित भंडार में वृद्धि कर दी। निवल FDI प्रवाह $21.3 बिलियन रहा और इसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार इसी अवधि में पत्राक निवेश के निवल प्रवाह के रूप में $8.2 बिलियन आगमन हुआ। जबकि गत वर्ष उसी अवधि में $3.5 बिलियन का पलायन हुआ था। बैंकों द्वारा विदेशी करेंसी संसाधान खरीदने के फलस्वरूप बैंकों की पूंजी में से $6.8 बिलियन विदेशों को प्रवाहित हो गए और बाह्य व्यापारिक ऋणों की वापसी पर भी 2016-17 के पूर्वार्द्ध में $4.6 बिलियन खर्च हुए। किन्तु फिर भी निवल पूंजी प्रवाह का आगमन CAD से अधिक रहा और BoP आधार पर भारत के विदेशी मुद्राकोष में निवल वृद्धि ही हुई (तालिका 8 और परिशिष्ट A1)।

विदेशी मुद्रा कोष

8.36 वर्ष 2016-17 के पूर्वार्द्ध में भारत के विदेशी मुद्रा कोष में $15.5 बिलियन की वृद्धि हुई (यह BoP आधार पर वृद्धि थी, अर्थात यह मूल्यांकन प्रभावों से इतर वृद्धि थी)। यदि मूल्यांकन प्रभावों सहित मौद्रिक रूप

में आंकलन करें तो इस वृद्धि का मान $11.8 बिलियन था। यह $3.7 बिलियन की हानि मुख्यत: विश्व की प्रमुख करेंसियों की तुलना में डालर के मान में वृद्धि का परिणाम थी।

विनिमय दर

8.37 FIIs के खाते पर, विशेषकर अंशपूंजी भाग में आगमन और संकुचित CAD के कारण एक सकारात्मक भावना का सृजन 2016-17 के पूर्वार्द्ध में हो रहा था। इसने रूपए में उतार-चढ़ाव को सीमित रखा। आगे के महीनों में रूपए के विनिमय मान में कमी के कारणों में प्रमुख थे : विश्व पटल पर डालर में सुधार, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और वहां की मौद्रिक नीति में संघीय रिजर्व द्वारा कसाव। अप्रैल-दिसंबर 2016-17 में वर्षानुगत आधार पर रूपए का विनिमय मूल्य डालर की तुलना में 3.4 प्रतिशत कम हुआ, जबकि मैक्सिको का पैसो 14.4 प्रतिशत, दक्षिण अफ्रीका का रैड 8.6 प्रतिशत तथा चीन का रेनमिन्नी 6.3 प्रतिशत कम हुआ था। अप्रैल-दिसंबर 2016-17 में रूपया 6 और 36 करेंसियों के स्थिर समूहों की तुलना में निवल प्रभावी विनिमय दर (NEER) के रूप में कम हुआ था। किन्तु 6 और 36 करेंसी के REER (व्यापार आधारित, आधार वर्ष 2004-05=100) में तो रूपए के मान में 6.1 तथा 5.6 प्रतिशत की क्रमश: वृद्धियां दर्ज हुई। यह वृद्धि मार्च 2016 के अंत से दिसंबर 2016 के अंत की अवधि में दर्ज की गई है।

VII. बाह्य ऋण

8.38 सितंबर, 2016 के अंत में भारत का बाह्य ऋण $484.3 बिलियन था, यह मार्च 2016 के अंत के ऋण से $0.8 बिलियन कम था। इसका मुख्य कारण व्यापारिक ऋणों और अल्पकालिक बाह्य ऋणों में कमी था। किन्तु यदि समय क्रम के हिसाब से चलें तो सितंबर 2016 का यह ऋणभार जून 2016 के अंत से $4.8 बिलियन अधिक भी था।

8.39 बाह्य ऋण में सरकारी (सार्वभौमिक) और गैर सरकारी ऋणों के अंश क्रमश: 20.1 और 79.9 प्रतिशत थे। अमेरीकी डालर में निर्दिष्ट ऋण भारत के सकल विदेशी ऋणों का 55.6 प्रतिशत (सितंबर अंत, 2016) थे। इनके बाद रूपयों में निर्दिष्ट (30.1 प्रतिशत) विशेष आहरण (3DRs) 5.8 प्रतिशत, जापानी येन, 4.8 प्रतिशत, पौंड स्टर्लिंग 0.7 प्रतिशत, यूरो 2.4 प्रतिशत और अन्य 0.6 प्रतिशत आंके गए थे।

8.40 यदि परिपक्कवता की दृष्टि से देखें तो भारत के बाह्य ऋणों में दीर्घकालिक उधार की ही बहुतायत है। सितंबर अंत, 2016 में दीर्घकालिक बाह्य ऋण कुल का 82.2 प्रतिशत था। परिपक्कवता की बची हुई अवधि की दृष्टि से अल्पकालिक ऋण सकल बाहरी ऋण का 42 प्रतिशत भाग थे और ये विदेशी मुद्रा भंडार के 54.7

तालिका 8 : भुगतान शेष खाते का सार ($ बिलियन)

	2013-14	2014-15	2015-16	2015-16	2016-17
		(अप्रैल-मार्च)		छमाही1	छमाही2
व्यापार संतुलन	-147.6	-144.9	-130.1	-71.3	-49.5
सेवाएं निवल	73.1	76.5	69.7	35.6	32.0
अदृश्य मदें (निवल)	115.2	118.1	107.9	56.7	45.7
चालू खाते का संतुलन	-32.4	-26.9	-22.2	-14.7	-3.7
सकल पूंजी/वित्त खाता (निवल)	47.9	88.3	40.1	25.3	19.2
सुरक्षित परिवर्तन ((-)वृद्धि, + कमी)	-15.5	-61.4	-17.9	-10.6	-15.5
व्यापार शेष/जीडीपी (प्रतिशत)	-7.9	-7.1	-6.3	-7.1	-4.6
अदृश्य शेष/जीडीपी (प्रतिशत)	6.2	5.8	5.2	5.7	4.3
चालू खाता शेष/जीडीपी (प्रतिशत)	-1.7	-1.3	-1.1	-1.5	-0.3
निवल पूंजी प्रवाह/जीडीपी (प्रतिशत)	2.6	4.3	1.9	2.5	1.8

स्रोत: आर.बी.आई.

प्रतिशत अंश के भी समान थे। सितंबर और जून 2016, दोनों के अंत में रियायती दरों पर मिले विदेशी ऋण का अंश 9 प्रतिशत था। बाह्य ऋण के मुख्य सूचक सितंबर 2016 में मार्च से इस दशा में सुधार के संकेत दे रहे हैं (तालिका 9)। सितंबर 2016 में सकल बाह्य ऋणों में अल्पकालिक ऋण का अंश 16.8 प्रतिशत रह गया था और देश का विदेशी विनिमय कोष सकल बाह्य ऋण के भंडार के 76.8 प्रतिशत का भुगतान करने में समर्थ था। अन्य सूचक भी कुछ न कुछ सुधार ही दिखा रहे थे।

8.41 विश्व बैंक के वार्षिक प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी International Debt Statistics, 2017 में विभिन्न देशों के बाह्य ऋणों ने 2015 के आंकड़े संकलित हैं। यह दिखा रहे हैं कि भारत विश्व के कम दुर्बलताग्रस्त देशों के वर्ग में है। अन्य ऋण ग्रस्त विकासशील देशों की तुलना में भारत के प्रमुख ऋण सूचक बेहतर दृश्य का चित्रांकन कर रहे हैं।

VIII. वर्ष 2017-18 में अर्थव्यवस्था की संभावनाएं

8.42 CSO ने अपने पहले अग्रिम अनुमान (AE) में इस वर्ष वर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहने की बात की है। किन्तु उसने यह भी स्पष्ट किया है कि यह अनुमान पहले 7 से 8 महीनों की जानकारी पर आधारित हैं। अत: इनके वितान से निश्चित रूप से विमुद्रीकरण का प्रभाव छूट ही गया होगा। वैसे जीडीपी पर उसके प्रभाव का सटीक अनुमान लगाना कठिन है फिर भी CSO अपने संशोधित/परिष्कृत आंकलन में जीडीपी और सकल मूल्य वृद्धि के अनुमानों को कुछ घटा सकती हैं यही नहीं स्फीति की दर भी प्रथम AE में निहित जीडीपी अपस्फायक से कम रह सकती है।

8.43 आशा है कि वर्ष 2017-18 में संवृद्धि दर अपने पुराने पथ पर लौट आएगी क्योंकि नए नोटों के रूप में पर्याप्त नकदी उपलब्ध हो जाएगी और विमुद्रीकरण के बाद वाले आवश्यक कदम उठा लिए जाएंगे। संवृद्धि क्रम को बनाए रखने में सहायक कारकों में संभावित सामान्य मानसून, वैश्विक संवृद्धि में पूर्वानुमानित वृद्धि के फलस्वरूप निर्यात में वृद्धि और अन्य सभी बातों से बढ़कर सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए अपनाए जाने वाले सुधार शामिल होंगे। वैसे संवृद्धि के पथ में आने वाली कुछ बाधाएं भी है। उदाहरण के लिए कच्चे तेल के दामों में वृद्धि प्रारंभ हो चुकी है और यह क्रम अगले वर्ष भी जारी रहने वाला है। अनुमान बताते हैं कि तेल कीमतें 2016-17 के स्तर से 16-17 प्रतिशत अधिक हो सकती है। इसका संवृद्धि पर कुछ नकारात्मक प्रभाव होगा। कई वर्षों से अर्थव्यवस्था में अचल पूंजी में निवेश (विशेषकर निजी क्षेत्र द्वारा), निरंतर कम हो रहा है। अर्थव्यवस्था की

तालिका 9 : भारत के बाह्य ऋणों के प्रमुख सूचक (प्रतिशत)

वर्ष	बाह्य ऋण +बिलियन	बाह्य ऋण जीडीपी अनुपात	ऋण सेवा अनुपात	रियायती ऋण सकल ऋण अनुपात	विदेशी मुद्राकोष और ऋण अनुपात	अल्पकाल विदेशी ऋण का विदेशी मुद्राकोष से अनुपात	अल्पकालिक ऋण और सकल विदेशी ऋण का अनुपात
2007-08	224.4	18.0	4.8	19.7	138.0	14.8	20.4
2013-14	446.2	23.9	5.9	10.4	68.2	30.1	20.5
2014-15	474.7	23.2	7.6	8.8	72.0	25.0	18.0
2015-16(PR)	485.0	23.4	8.8	9.0	74.3	23.1	17.2
सितम्बर, 2016 की समाप्त अवधि (त्वरित अनुमान)	484.3	*	*	9.4	76.8	21.8	16.8

स्रोत: अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग
टिप्पणी: A = उत्पादन 170 किलोग्राम प्रत्येक की मिलियन गांठों में हैं।
खरीफ और रबी फसलों के अंतर्गत भूक्षेत्र

संवृद्धि दर को ऊपर उठाने के लिए निवेश की इस प्रवृति को वापस मोड़ना अत्यंत आवश्यक रहेगा, पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक व्यापार और निवेश प्रवाहों में भी शिथिलता आई है। वैसे अभी तक भारत इस शिथिलता से अछूता रहा है, किन्तु विदेशी पत्राक निवेश की वृद्धि कम रह जाने की पूरी आशंका है (इसका एक कारण तो यही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्याज की दरों में सुधार होने लगा है)।

8.44 कुल मिलाकर पूरी-पूरी संभावना है कि 2017-18 में भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से 6 (3/4) से 7 (1/2) प्रतिशत के संवृद्धि पथ पर लौट आएगा।

IX. कृषि और खाद्य प्रबंधन

8.45 सीएसओ के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार 2016-17 में कृषि की संवृद्धि दर 4.1 प्रतिशत रहेगी। विवरण तालिका 10 में है।

उत्पादन

8.46 कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा 22 सितंबर, 2016 को जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष में खरीफ की फसल में खाद्य उत्पादन 135.0 मिलियन टन रहेगा। यह 2015-16 के 124.1 मिलियन टन से अधिक है (तालिका 10)।

तालिका 10 : प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन (मिलियन टनों में)

फसलें	2015.16 (First AE)	2016.17 (First AE)
सकल खरीफ, खाद्य फसलें	124.1	135.0
चावल	90.6	93.9
सकल मोटे अनाज	27.9	32.5
सकल दालें	5.6	8.7
सकल तेलीय बीज	19.9	23.4
गन्ना	341.4	305.2
कपास	33.5	32.1

स्रोत: अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग

टिप्पणी : a = उत्पादन 170 किलोग्राम प्रत्येक की मिलियन गांठों में हैं।

खरीफ और रबी फसलों के अंतर्गत भूक्षेत्र

8.47 अक्टूबर 14, 2016 तक सभी खरीफ फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल 1057.7 लाख हेक्टेयर रहा। यह पिछले वर्ष (2015-16) के 1039.7 लाख हैक्टेयर से 3.5 प्रतिशत अधिक है (परिशिष्ट 2)। अरहर में 2016-17 के खरीफ में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है।

8.48 रबी की बुआई अभी चल रही है। जनवरी 13, 2017 तक 616.21 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल पर बुआई हो चुकी है। यह पिछले वर्ष के इसी सप्ताह तक, से 5.9 प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल है (रेखाचित्र 13)। इसी 13 जनवरी तक गेहूँ की फसल पिछले वर्ष की तुलना में 7.1 प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल पर लगाई गई है। चने की खेती भी इसी प्रकार पिछले वर्ष से 10.6 प्रतिशत अधिक भूमि पर हो रही है (रेखाचित्र 13, अध्याय 1)।

8.49 वर्ष 2016 के दक्षिण पश्चिम मानसून काल (जून-सितंबर) में पूरे देश में दीर्घकालिक औसत (LPA) के 97 प्रतिशत के समान वर्षा हुई। इस अवधि में वास्तव में 860.0 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जबकि LPA 887.5 मिलीमीटर है। क्षेत्रवार वर्षा का विवरण तालिका 11 में दिया गया ह। देश के 36 मौसम उपसंभागों में से 4 में अतिवृष्टि हुई, 23 में सामान्य और शेष 9 में कुछ वृष्टि अभाव रहा।

तालिका 11 : दीर्घकालिक औसत बनाम वास्तविक दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा (जून-सितंबर 2016)

क्षेत्र	LPA (mm)	Rainfall (mm) (Actual)	Rainfall (% of LPA)
भारत वर्ष	887.5	862.0	97
उत्तर-पश्चिम भारत	615.1	584.2	95
मध्य भारत	975.3	1034.1	106
उत्तर-पूर्वी भारत	1437.8	1281.5	89
दक्षिण प्रायद्वीप	715.6	661.5	92

स्रोत: भारतीय मौसम विभाग

मुख्य फसलों का सिंचाई के अधीन क्षेत्रफल

8.50 सिंचाई कृषि में उत्पादिता सुधार के लिए एक निर्णायक आदान होता है। सिंचित क्षेत्र के फसलानुसार वितरण में बहुत भारी अन्तर देखे जा सकते हैं (रेखाचित्र 14)।

कृषि उत्पादों के लिए कीमत नीति

8.51 सरकार की मुख्य फसलों के लिए कीमत निर्धारण नीति के ध्येय है : किसान को लाभप्रद कीमत दिलाना, उच्चतर निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहन देना और उचित दाम पर कृषि उत्पादों की आपूर्ति सुलभ कराते हुए उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करना। दालों की कीमतों में उच्चावचन के कारण ''न्यूनतम समर्थन कीमत के माध्यम से दालों के उत्पादन की प्रेरणाएं प्रदान करने'' के उद्देश्य से मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. अविन्द सुब्रमण्यम की अधयक्षता में एक समिति का सार गठन किया गया और उसने अपनी रिपोर्ट (सितंबर 16, 20; क,ख) सरकार को सौंप दी थी। समिति की मुख्य सिफारिशें परिशिष्ट में A3 दी गई हैं। पूरी रिपोर्ट http://mof.gov.in/reports/Pulses_report_16th_sep_2016.pdf पर उपलब्ध है। दालों की उत्पादिता बढ़ाने के लिए अरहर की अति अगेती, उच्च उत्पादिता किस्म (पूसा अरहर-II) का विकास हो चुका है और अगले खरीफ के मौसम में वह बीज किसानों को उपलब्ध हो जाएंगे।

8.52 परिशिष्ट A-4 में सभी प्रमुख फसलों की न्यूनतम समर्थन कीमतों का विवरण दिया गया है। वर्ष 2016-17 में किसानों को दालें उत्पादित करने का प्रोत्साहन देने के लिए उनकी समर्थन कीमतों में अच्छी खासी वृद्धि की गई है (रेखाचित्र 15)।

खाद्यान्न भंडार और केन्द्रीय अन्न भंडार के लिए प्रापण

8.53 खाद्यान्न प्रबंधन में चावल और गेहूं के सुरक्षित भंडारण के नियमों का पालन करते हुए इन उत्पादों की बाजार से फसल के मौके पर सरकार द्वारा खरीदारी महत्वपूर्ण होती है। दिसंबर 1, 2016 को चावल और गेहूं के भंडार 43.5 मिलियन टन थे, यह वर्ष पूर्व 50.5 मिलियन टन से कम थे। किन्तु सुरक्षित भंडार मानको (अक्टुबर 1, 2015) के अनुसार इनका 30.77 मिलियन टन होना ही पर्याप्त रहता (रेखाचित्र 16क, 16ख)। जनवरी 6, 2017 को रबी 2016-17 के बाजार आने पर चावल की 23.2 मिलियन टन मात्र की खरीदारी सरकार कर चुकी थी। उपभोक्ता के हितों की दृष्टि से केन्द्र द्वारा अपने भंडार से माल जारी करते समय चावल और गेहूँ के दाम जुलाई 1, 2002 से अपरिवर्तित रहे हैं।

कृषि साख/ऋण

8.54 कृषि उत्पादन एवं उत्पादिता को सुधारने के लिए साख सुविधा एक महत्वपूर्ण आदान होती है। कृषि की ओर साख प्रवाह बढ़ाने के लिए 2016-17 में कृषि साख लक्ष्य 9 लाख करोड़ रूपए रखा गया है। यह गत वर्ष के 8.5 लाख करोड़ के लक्ष्य से अधिक है (रेखाचित्र 17)। इस लक्ष्य की दिशा में सितंबर 2016 तक 84 प्रतिशत साख वितरण हो चुका था। यह भी 2015 के सितंबर के 59 प्रतिशत से कहीं अधिक है।

रेखाचित्र 13 : रबी की फसलों की बुआई (मिलियन हैक्टेयर)

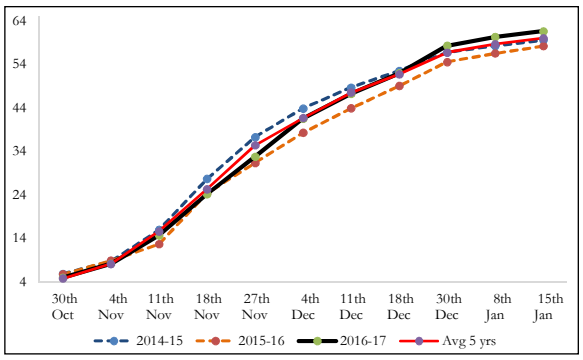

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

रेखाचित्र 14 : मुख्य फसलों के अधीन सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत फैलाव, 2013-14 राज्यवार

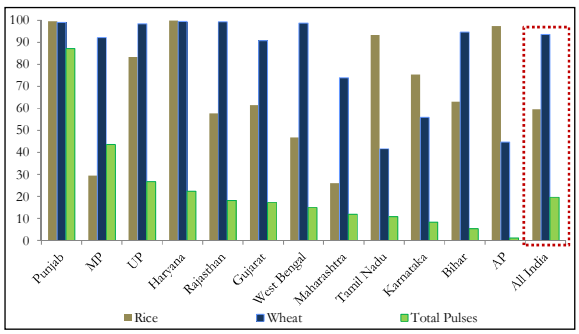

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

X. औद्योगिक, निगम और संरचना क्षेत्रक

8.55 सीएसओ के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार खान खदान, विनिर्माण, विद्युत और निर्माण उद्योगों की संवृद्धि दर 2015-16 की 7.4 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 5.2 प्रतिशत रह जाने की आशंका है (देखें तालिका-1, अनुच्छेद 8.3)। अप्रैल-नवंबर 2016-17 में औद्योगिक उत्पादन सूचक में मामूली सी वृद्धि, 0.4 प्रतिशत, दिखाई दी है। यह एक परिमाण सूचक है, जिसका आधार वर्ष 2004-05 है। यह बिजली उत्पादन में तीव्र दर से वृद्धि किन्तु खनन और विनिर्माण में कुछ शिथिलता का मिलाजुला परिणाम रहा है (तालिका 12)। प्रयोजन आधारित वर्गीकरण पर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि आधारिक वस्तुओं, मध्यवर्ती और उपभोक्ता दीर्घोपयोगी वस्तुओं में सामान्य सी वृद्धि हुई है। किन्तु इनके विपरीत पूंजीगत पदार्थों में तीखी और गैर दीर्घोपयोगी उपभोक्ता वस्तुओं में सामान्य गिरावट आई है (अप्रैल-नवंबर 2016-17, तालिका 12)।

8.56 आठ प्रमुख आधार संरचना समर्थक उद्योगों अर्थात कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, परिशोधन उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली का IIP में 38 प्रतिशत भारमान है और इन उद्योगों में 4.9 प्रतिशत दर से अप्रैल-नवंबर 2016-17 में संचयी संवृद्धि हुई है, जबकि गत वर्ष की इसी अवधि में यह संवृद्धि मान 2.5 प्रतिशत रहा था। परिशोधन उत्पादों, उर्वरकों, इस्पात, बिजली और सीमेंट के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है किन्तु इस अप्रैल-नवंबर 2016-17 की अवधि में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कमी आई है। इसी अवधि में कोयले की संवृद्धि दर भी कम रही है।

तालिका 12 : IIP के आधार पर प्रमुख क्षेत्रीय वृद्धि दरों के उपभोग आधारित वर्गीकरण
(प्रतिशत)

	2014-15	2015-16	अप्रैल-नवंबर 2015.16	अप्रैल-नवंबर 2016-17
सामान्य सूचक	2.8	2.4	3.8	0.4
खनन	1.5	2.2	2.1	0.3
विनिर्माण	2.3	2.0	3.9	-0.3
विद्युत	8.4	5.7	4.6	5.0
आधारभूत वस्तुएं	7.0	3.6	3.9	4.1
पूंजीगत पदार्थ	6.4	-2.9	4.7	-18.9
मध्यवर्ती वस्तुएं	1.7	2.5	2.0	3.4
उपभोक्ता वस्तुएं	-3.4	3.0	4.1	1.8
स्थायी प्रयोग वस्तुएं	-12.6	11.3	11.8	6.9
गैर स्थायी वस्तुएं	2.8	-1.8	-0.5	-1.8

स्रोत : **CSO**

8.57 संरचना क्षेत्रक संबंधी सभी गतिविधियों ने 2016-17 के पूर्वार्द्ध में प्रसार का प्रदर्शन किया है। ताप विद्युत उत्पादन ने 6.9 प्रतिशत से संवृद्धि कर सकल विद्युत उत्पादन के स्तर को ऊंचा उठा दिया है, जबकि इसी अप्रैल-सितंबर 2016 की अवधि में जल एवं नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में कुछ संकुचन ही हुआ था (रेखाचित्र 18)।

8.58 जनवरी 2017 की रिजर्व बैंक की जानकारी के अनुसार निगम क्षेत्र के निष्पादन की बड़ी विशेषता 2016-17 की दूसरी तिमाही में बिक्री में 1.9 प्रतिशत की वृद्धि रही। पहली तिमाही में तो यह नगण्य प्राय: 0.1 प्रतिशत पर ही टिकी रही थी। दूसरी तिमाही में कार्य से लाभ की संवृद्धि कुछ धीमी होकर 5.5 प्रतिशत रह गई, जबकि पिछली ही तिमाही में वह 9.6 प्रतिशत थी। ब्याज व्यय में वर्षानुगत आधार आंकलित वृद्धि दूसरी तिमाही में समतल ही रही। जबकि पहली तिमाही में इसमें 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी थी। हां, 2016-17 की दूसरी तिमाही में निवल लाभ में बहुत शानदार 16 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह पहली तिमाही की 11.2 प्रतिशत से भी उच्चतर है।

8.59 सरकार ने प्रतिरक्षा, रेल संरचना, निर्माण और औषध आदि क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति को सरल और उदार बना दिया है। अप्रैल-सितंबर 2016 में FDI शेयर पूंजी के रूप में $21.7 बिलियन की राशियों का देश में प्रवाह आया, जबकि 2015 में उसी अवधि में $16.6 बिलियन राशियां आई थीं। यह 30.7 प्रतिशत का बड़ा उछाल है। सेवा, निर्माण विकास, कम्प्यूटर के हार्ड एवं सॉफ्टवेयर तथा दूर संचार क्षेत्रों ने अधिकतम FDI शेयर पूंजी प्रवाहों को आकर्षित किया है।

रेखाचित्र 15 : चुनी हुई फसलों की न्यूनतम समर्थन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन (2015-16 की तुलना में 2016-17 में)

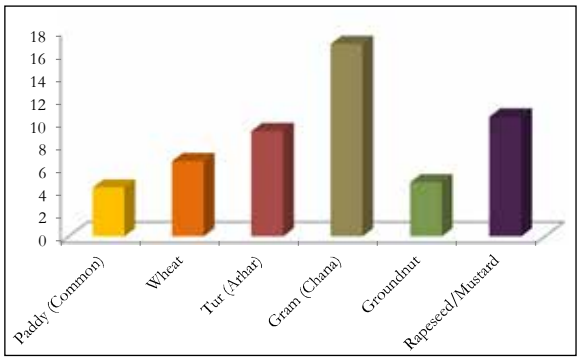

स्रोतः कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी)

8.60 सरकार ने देश में निवेश/व्यापार करने को सुविधाजनक बनाने की दिशा में कई नए कदम उठाए हैं। इनमें प्रमुख हैं : भारत में निर्माण करो, निवेश भारत, स्टार्टअप इंडिया और राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना के अंतर्गत e-biz मिशन प्रकल्प। व्यवसाय व्यापार को सुविधापूर्ण बनाने की दृष्टि से औद्योगिक सहमति पत्र की e-biz वेबसाईट के जरिए उद्यमियों को 22x7 कार्य कर पाने की सुविधा दी गई है। साथ ही इन दोनों कार्यों के लिए आवेदन पत्रों को सरल बनाने तथा विदेश व्यापार महानिर्देशन द्वारा निर्यात आयात की अनुमति हेतु मांगे जाने वाले दस्तावेजों को तीन तक सीमित करने के साथ-साथ निवेश भारत के अंतर्गत निवेशक सुविधा प्रकोष्ठ की स्थापना कर व्यवसाय के पूरे जीवन चक्र में निवेशकों को मार्गदर्शन और साथ देने की व्यवस्था बनाई गई है।

XI. सेवाओं का क्षेत्र

8.61 सीएसओ के प्रथम अनुमान ने 2016-17 में सेवा क्षेत्र की संवृद्धि 8.8 प्रतिशत रहने की आशा व्यक्त की है, यह लगभग 2015-16 वाली ही दर है (देखें तालिका 1, अनुच्छेद 8.3)। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार भारत का व्यापारिक सेवा निर्यात 2005 के $51. 9 बिलियन से बढ़कर 2015 में $155.3 बिलियन हो चुका है। विश्व सेवा निर्यात में भारत का अंश 2014 के 3.1 प्रतिशत से बढ़कर 2015 में 3.3 प्रतिशत हो गया, जबकि 2014 की 5 प्रतिशत संवृद्धि के स्थान पर 2015 में तो संवृद्धि दर (-) 0.2 प्रतिशत ही रही थी। इसका कारण विश्व सेवा निर्यात में 2015 में कहीं अधिक भारी

रेखाचित्र 16क : गेहूं के भंडार तथा सुरक्षित भंडार मानक (मिलियन टनों में)

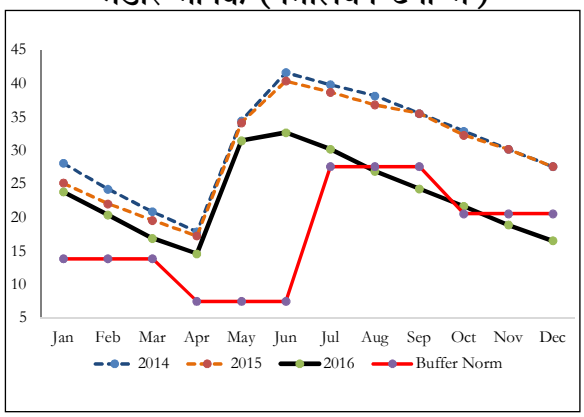

स्रोत : भारतीय खाद्य निगम

रेखाचित्र 16ख : चावल भंडार और सुरक्षित भंडार मानक (मिलियन टनों में)

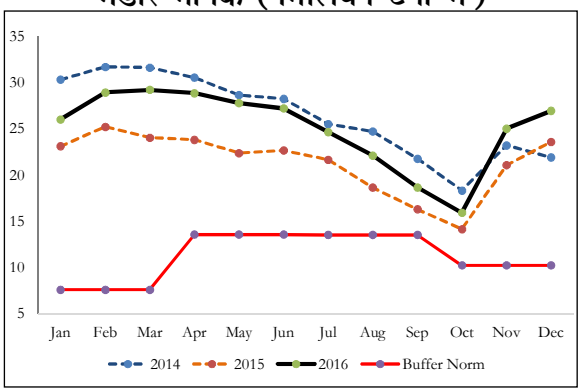

स्रोत : भारतीय खाद्य निगम

रेखाचित्र 17: कृषि साख (लाख करोड़ रूपए में)

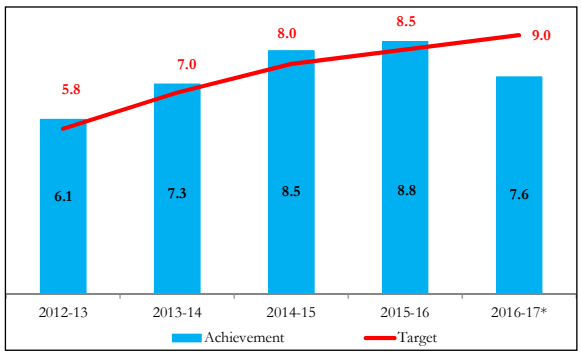

***स्रोत :* नाबार्ड**

***टिप्पणी :* *वर्ष 2016-17 के लिए लक्ष्य पूर्ण वर्ष को दर्शाता है जबकि उपलब्धि पहली छमाही के लिए है।**

गिरावट (-)6.1 प्रतिशत होना था। रिजर्व बैंक के BoP आधार के आंकड़ों के अनुसार 2015-16 में भारत के सेवा निर्यातों में 2.4 प्रतिशत की कमी आई थी। इसका कारण विश्व उत्पादन एवं व्यापार में शिथिलता बताया

रेखाचित्र 18 : वर्ष 2016-17 के पूर्वार्द्ध में संरचना संबंधि कार्यों में वृद्धि (प्रतिशत)

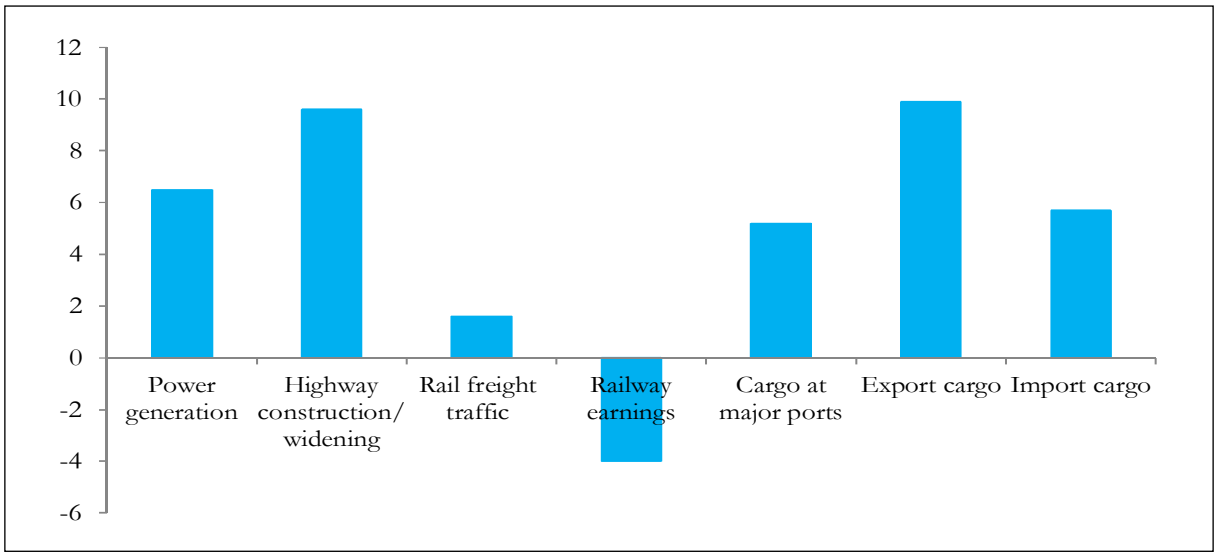

स्रोत: एमओएसपीआई

गया था। किन्तु 2016-17 के पूर्वार्द्ध में सेवा निर्यात में 4.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की 0.3 प्रतिशत वृद्धि से कई गुना अधिक है। भारत के वस्तु व्यापार शेष के घाटे की भरपाई करने वाले मुख्य निवल सेवा निर्यात क्षेत्र में 2015-16 के पूर्वार्द्ध में (-)9.0 प्रतिशत और 2016-17 में (-)10.0 की ऋणात्मक संवृद्धि हो पाई है। इसका मुख्य कारण देश में सेवाओं के आयात में आया उछाल है। सेवा निर्यात में 48.1 प्रतिशत योगदान देने वाले सॉफ्टवेयर उपक्षेत्रक की संवृद्धि दरें तो 2015-16 और 2016-17 के पूर्वार्द्धों में क्रमश: बहुत ही निराशाजनक, 1.4 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत ही रही।

8.62 भारत के पर्यटन क्षेत्र ने भी विदेशियों के आगमन में अच्छी वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2015 में 8.2 मिलियन विदेशी पर्यटक भारत आए। यह पिछले वर्ष से 4.5 प्रतिशत की वृद्धि थी। पर्यटकों से विदेशी मुद्रा की कमाई भी 4.1 प्रतिशत वृद्धि के साथ $21.1 बिलियन हो गई थी। जनवरी-दिसंबर 2016 में भारत में 8.9 मिलियन विदेशी सैलानी आए। यह 10.7 प्रतिशत की वृद्धि रही है। उन पर्यटकों का भारत के व्यय पिछले वर्ष से 9.8 प्रतिशत अधिक, अर्थात $23.1 बिलियन रहा।

8.63 निक्केई मार्किट सर्विसेज का PMI भारत के लिए जनवरी 2013 में एक उच्चमान, 57.5 दिखा रहा था। यह नवंबर 2016 में 46.8 पर आ गया जबकि एक मास पहले ही इसका मान 56.5 था। फिर भी दिसंबर में यह थोड़ा सा सुधार कर 46.8 हो गया। बल्टिक ड्राई सूचक वस्तु व्यापार और जहाजरानी सेवाओं के परिवर्तन दर्शाता है। इसमें नवंबर 18, 2016 तक कुछ वृद्धि हो रही थी किन्तु जनवरी 13, 2017 को यह कम होकर 910 रह गया था (रेखाचित्र 19)।

XII. सामाजिक उपरि संरचना, रोजगार और मानवीय विकास

सामाजिक क्षेत्रीय व्यय की प्रवृत्तियां

8.64 रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार केन्द्र और राज्यों का सामाजिक क्षेत्र पर व्यय जीडीपी के 7.0 प्रतिशत के समान रहने का अनुमान 2016-17 के बजट में रखा गया था। इसमें शिक्षा का अंश 2.9 प्रतिशत और स्वास्थ्य का अंश 1.4 प्रतिशत रखा गया था (तालिका 13)। हमारे पास वर्ष 2014-15 के वास्तविक व्यय के आंकड़े उपलब्ध है और ये रिजर्व बैंक द्वारा दर्शाए गए स्तर से काफी कमी दिखा रहे हैं। इसका मुख्य कारण राज्यों द्वारा सामाजिक क्षेत्र पर अपने संशोधित अनुमानों से भी कम व्यय करना रहा।

रेखाचित्र 19 : बल्टिक ड्राई सूचक

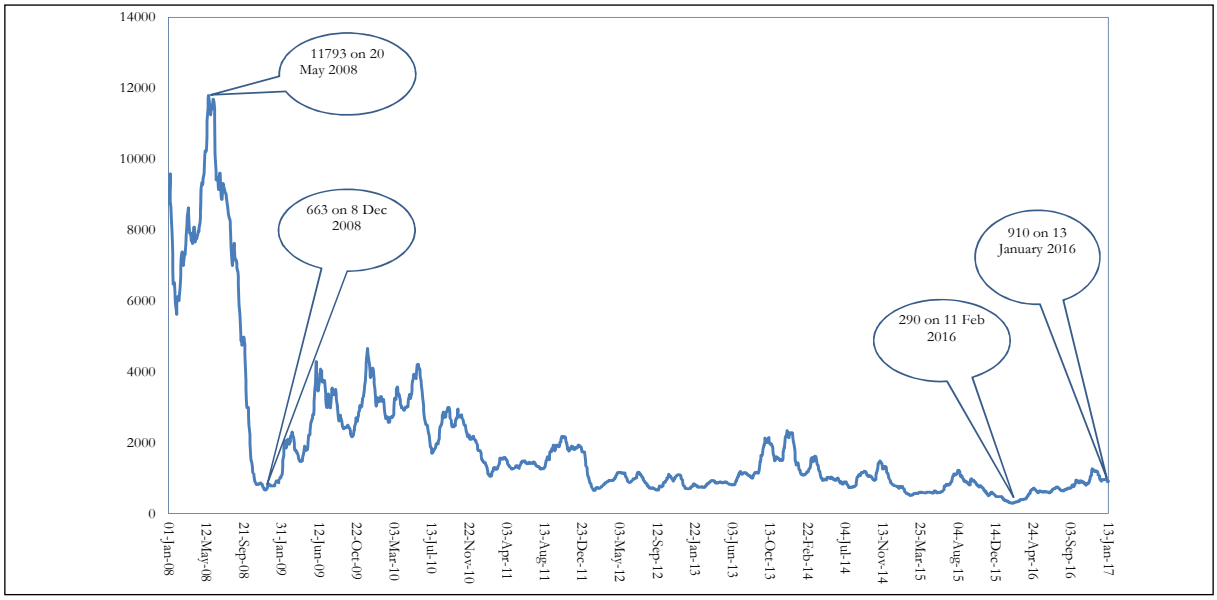

Source: http://in.investing.com/indices/baltic-dry-historical-data

रोजगार परिदृश्य

8.65 श्रम ब्यूरो द्वारा दिसंबर 2015 में कुछ चुने हुए श्रम सघन और निर्यातोन्मुखी क्षेत्रों का त्रैमासिक तुरंत सर्वेक्षण कर दिसंबर 2014 की स्थिति से तुलना करते हुए रोजगार में 135 हजार की वृद्धि का अनुमान लगाया था (रेखाचित्र 20)। इसमें योगदान देने वाले क्षेत्र रहे आईटी/बीपीओ, वस्त्र-परिधान और धातु। किन्तु जवाहरात और आभूषण, पॉवरलूम/हैंडलूम, चर्म उद्योग, वाहन निर्माण और परिवहन में इस अवधि में रोजगार में कमी ही हुई थी।

8.66 वार्षिक रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण EUS (इन्हें भी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा ही आयोजित किया जाता है) श्रम रोजगार संबंधी आंकड़ों के लिए कहीं अधिक व्यापक सूचना सूत्रों का प्रयोग करते हैं। नवीनतम EUS की 2015-16 की जानकारी तालिका 14 में प्रस्तुत की गई है। सामान्य मुख्य अवस्था की कसौटी के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर श्रम शक्ति में भागीदारी दर 50.3 प्रतिशत आंकी गई है। महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी दर पुरूषों की तुलना में बहुत कम है। इस महिला भागीदारी में राज्यानुसार भी बहुत अन्तर स्पष्ट होते हैं। उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी राज्यों में श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी दर उत्तरी राज्यों की अपेक्षा कहीं अधिक है। EUS 2015-16 के अनुसार शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी दर पुरूषों की अपेक्षा अधिक थी (तालिका

तालिका 13 : सामाजिक क्षेत्र पर व्यय में प्रवृत्तियां

मदें	2009-10	2013-14	2014-15	2015-16 स.अ.	2016-17 ब.अ.
			स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में		
कुल व्यय	28.6	26.6	25.1	28.2	28.4
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	6.9	6.6	5.7	6.9	7.0
जिनमें से					
शिक्षा	3.0	3.1	2.6	2.9	2.9
स्वास्थ्य	1.4	1.2	1.1	1.3	1.4
अन्य	2.5	2.3	2.0	2.7	2.7

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

14)। बेरोजगारी दरों में भी राज्यानुसार बहुत अंतर है (देखें रेखाचित्र 21)।

8.67 EUS सर्वेक्षण दर्शा रहे हैं कि रोजगार संवृद्धि धीमी रही है। यही नहीं जिन प्रदेशों में विनिर्माण उद्यमों का अनुक्रम उच्च है, वहां बेरोजगारी भी कम है। वैसे तो राज्य निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन के साथ जुड़ी संप्रेरणाए प्रदान करने के पटल पर परस्पर स्पर्धा कर रहे हैं, फिर भी रोजगार संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

8.68 रेखाचित्र 22क और ख में रोजगार को क्षेत्रों और वर्गों के अनुसार अंकित किया गया है। प्राथमिक से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की ओर रूझान बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वर्गानुसार रोजगार संवृद्धि में अनियमित और ठेका मजदूरों की संख्याओं में वृद्धि बहुत स्पष्ट है (रेखाचित्र 22ख)। इसके मजदूरी दरों, रोजगार में स्थायित्व और कर्मचारियों के लिए सुलभ सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत ही नकारात्मक निहित प्रभाव रहते

रेखाचित्र 20 : आठ चुने हुए क्षेत्रों में रोजगार परिवर्तन के अनुमान (दिसंबर, 2014 से दिसंबर 2015 तक)

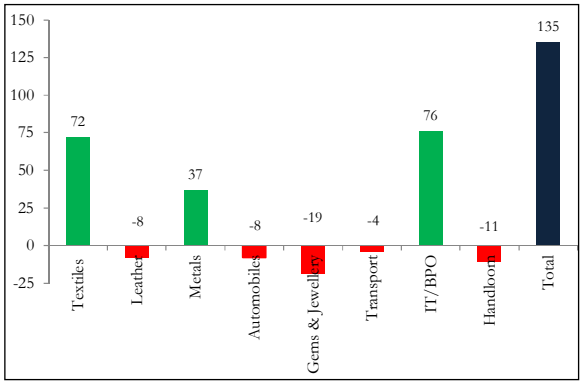

स्रोत : श्रम ब्यूरो

हैं, क्योंकि यह रोजगार तो स्वयं ही अस्थायी प्रकृति का होता है। यह रोजगार दाताओं की श्रम कानूनों से बचकर निकलने की युक्तिगत वरीयता भी दिखाता है।

8.69 श्रम कानूनों की बहुलता और उनके अनुपालन में आने वाली कठिनाइयां औद्योगिक विकास और रोजगार संवर्धान में बाधाक रही हैं। इस समय देश में केन्द्रीय स्तर पर 39 श्रम कानून चल रहे है जिन्हें कार्यों के आधार पर 4 या 5 श्रम संहिताओं में वर्गीकृत करने के सुझाव दिए गए हैं, साथ ही छोटी विनिर्माण इकाइयों के लिए विशेष कानून होना चाहिए। व्यवस्था का संपूर्ण रूप से पालन, रोजगार सृजन की आवश्यकता को समझने और श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सभी कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए व्यवसाय करना सरल बनाने के लक्ष्य को लेकर बड़ी पहल करते हुए सरकार ने अनेक श्रम सुधार उपाय सुझाए हैं।

शिक्षा क्षेत्र

8.70 स्कूली शिक्षा के संदर्भ में प्राय: शिक्षार्थियों के निम्न ज्ञान को लेकर एक महत्वपूर्ण चिन्ता बार-बार व्यक्त की गई है। यह ASER, 2014 सहित अनेक अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है। शिक्षार्थियों के स्कूल में पहुँच पाने और उनके व्यवस्था से जुड़े रहने में तो सुधार हुए हैं पर इस विषय में अभी भी चिंताएं हैं कि क्या उनमें से अधिकांश कुछ सीख भी पाते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता के निम्न स्तर के लिए उत्तरदायी कारणों में शिक्षकों की अनुपस्थिति और प्रशिक्षित शिक्षकों के अभाव प्रमुख पाए गए हैं।

8.71 यद्यपि सर्व शिक्षा अभियान पर व्यय में 'शिक्षक' पर खर्च का अंश 2011-12 के 35 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 59 प्रतिशत हो चुका है, फिर भी शिक्षक

तालिका 14 : LFPR, WPR तथा UR% सामान्यमुख्य दशानुसार (UPS) 2015-16

मानदंड	ग्रामीण			शहरी			कुल		
	M	F	P	M	F	P	M	F	P
LFPR	77.3	26.7	53.0	69.1	16.2	43.5	75.0	23.7	50.3
WPR	74.1	24.6	50.4	66.8	14.3	41.4	72.1	21.7	47.8
UR	4.2	7.8	5.1	3.3	12.1	4.9	4.0	8.7	5.0

स्रोत: पांचवी वार्षिक EUS रिपोर्ट, श्रम ब्यूरो, 2015-16

नोट: LFPR = श्रमशक्ति भागीदारी दर, WPR = श्रमिक जनसंख्या अनुपात, UR = बेरोजगारी दर, M = पुरूष, F = महिलाएं, P = व्यक्ति

रेखाचित्र 21 : 2015-16 में विभिन्न राज्यों में 15 वर्ष से अधिक आयुवर्ग में न्यै विधि के अनुसार बेरोजगारी दरें (प्रतिशत)

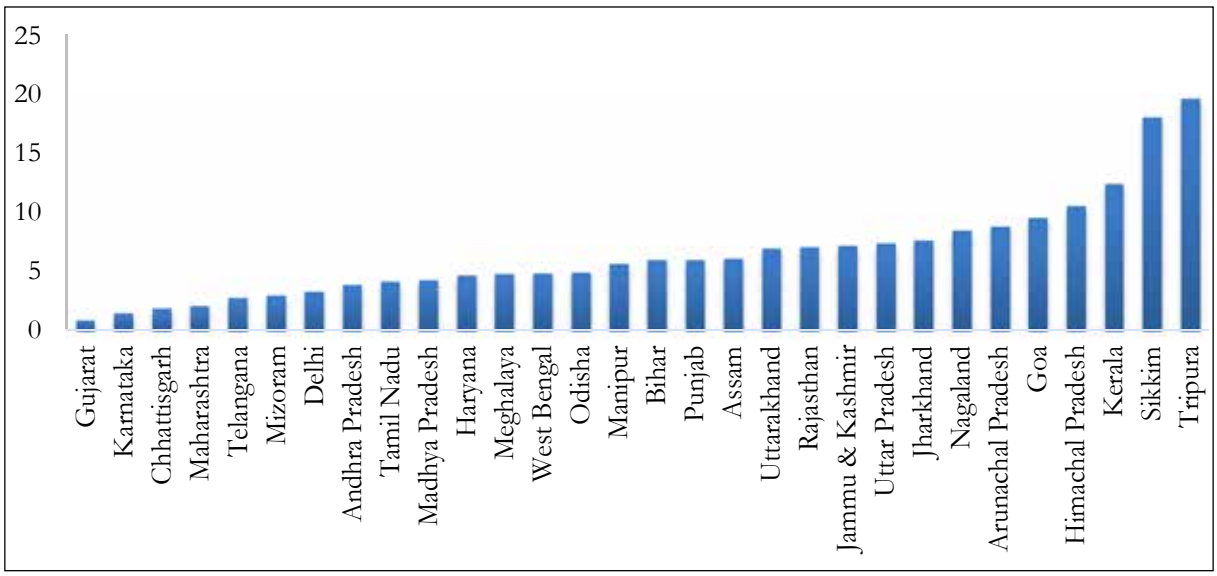

स्रोत: 5वें वार्षिक ईयूएस, 2015-16 संबंधी रिपोर्ट (श्रम ब्यूरो)

रेखाचित्र 22क एवं ख :रोजगार के क्षेत्र और वर्गानुसार न्यै विधि से भारत भर में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का आबंटन (प्रतिशत)

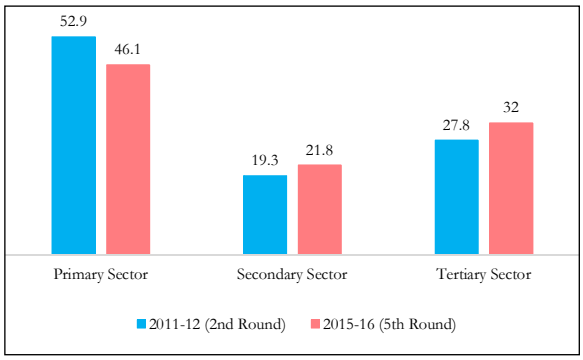

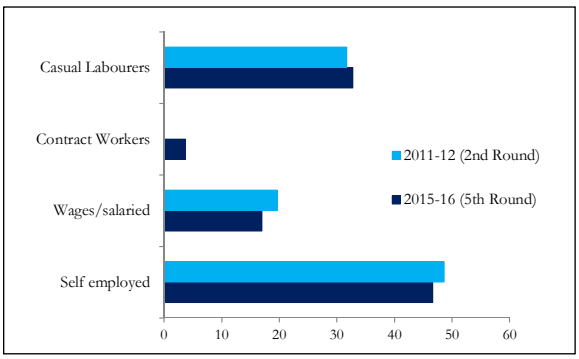

स्रोत: 5वें वार्षिक ईयूएस, 2015-16 संबंधी रिपोर्ट (श्रम ब्यूरो)

की अनुपस्थिति एवं व्यवसायिक रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों के अभाव की समस्या अभी ज्यों की त्यों बनी हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के 2014-15 के बजट के घटक रेखाचित्र 23 में दिखाए गए हैं।

8.72 शिक्षकों की अनुपस्थिति की समस्या का एक समाधान प्राथमिक स्कूलों के प्रत्येक शिक्षक की सभी निर्धारित कक्षाओं/आख्यानों/कार्यों में उपस्थिति की बायोमैट्रिक प्रणाली अपनाने का सुझाव हो सकता है। यह उस वर्तमान व्यवस्था से अलग हो सकता है, जहां सुबह शाम शिक्षक के आने और जाने का तो हिसाब रहता है, पर उसने दिन भर क्या किया और क्या नहीं किया पर कोई नियंत्रण नहीं होता। सभी राज्यों के एक-एक जिलों में 6 महीनों के लिए इस प्रकार के अध्ययन प्रकल्प चलाए जा सकते हैं और परिणाम अच्छे रहने पर उसे तीन वर्षों में सभी जिलों में लागू किया जा सकता है। इस बायोमैट्रिक उपस्थिति पर स्थानीय समुदाय और अभिभावकों की निगरानी के साथ-साथ इस जानकारी को सार्वजनिक भी किया जाना चाहिए। इनके साथ-साथ पर्याप्त शिक्षण सामग्री एवं उपस्कर, पहले से ही रिकार्ड किए गए लैक्चर/आख्यान आदि भी तैयार होने चाहिए ताकि किसी शिक्षक के नहीं आने पर भी शिक्षण-अध्ययन चल सके। सारे प्रकल्प के संचालन में स्कूल पर नम्यता भी होनी चाहिए ताकि इसका हाल भी

कभी ऊपर से संचालित 'आदर्श विद्यालयों' जैसा नहीं हो। शिक्षकों की बायोमैट्रिक उपस्थिति रिकार्ड करने के शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन पर प्रभावों की भी समीक्षा होनी चाहिए।

सबके लिए स्वस्थता

8.73 भारत की स्वास्थ्य नीति एक समेकित विधि अपनाने पर आग्रह करती है जो समाज के सीमांत एवं अभावग्रस्त वर्गों को कम खर्चीली एवं समतापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सहज सुलभ करा पाए। धारणीय विकास लक्ष्य-3 ने सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली का विचार इस प्रकार निरूपित किया है, ''सभी के लिए सभी आयु बिन्दुओं पर अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली सुनिश्चित करें''। इस विचार का भारत के 'जनांकीय लाभांश' के हितलाभ प्राप्त करने के लिए निश्चित किए गए लक्ष्यों के साथ समन्वय किया जाना चाहिए।

8.74 यद्यपि सरकार द्वारा सभी के वह (कम खर्चीली) स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में अनेक समस्याएं/बाधाएं आयी हैं किन्तु उनके बाद भी स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां भी हुई हैं। जीवाशा में वृद्धि हुई है और शिशु मृत्यु दर एवं अपरिष्कृत मृत्यु दरों में भारी कमी आई है। भारत की सकल गर्भाधान दर (TFR) निरंतर घटती रही है। यह 2014 में 2.3 रही (शहरों में 1.8, गांवों में 2.5)। शिशु मुत्यु दर (IMR) 2011 की 44 प्रति हजार जीवित जन्म से घटकर 2015 में 37 रह गई है। अब सबसे बड़ी चुनौति शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बड़े अंतर का दूर करने की है : शहरों में IMR 25 प्रति हजार हो चुका है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी यह 41 प्रति हजार जीवित जन्म पर अटका हुआ है।

8.75 प्रसव मृत्यु दर (MMR) प्रति एक लाख जीवित प्रसव का स्तर 2001-03 में 301 था। यह 2011-13 में घटकर 167 रह गया है। किन्तु MMR के स्तर में क्षेत्रीय विविधताएं बहुत विशाल हैं (रेखाचित्र 24), असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की यह MMR राष्ट्रीय औसत 164 से कहीं अधिक है। अत: SDR-3 के अनुरूप महिलाओं के स्वस्थता और पोषण में सुधार के साथ अखिल

रेखाचित्र 23 : सर्वशिक्षा अभियान के बजट के घटक (प्रतिशत अंश), 2014-15

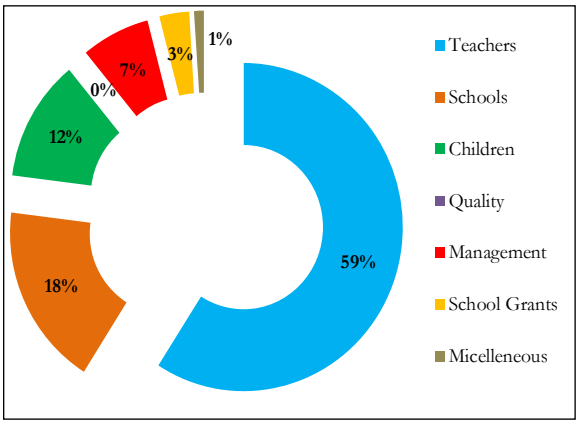

स्रोत: एसएसए पोर्टल, एएसईआर पोर्टल

भारतीय MMR में और कमी लाने के साथ-साथ हमें उच्च MMR वाले प्रांतों में इस दर को तेजी से घटाकर राष्ट्रीय औसत के निकट लाने पर अधिक ध्यान देना होगा।

8.76 आयु वर्ग 15-45 की महिलाओं में रक्ताल्पता (खून की कमी) के उच्च स्तर का MMR से सीधा सहसंबंध रहता है। हरियाणा और पश्चिम बंगाल में 60 प्रतिशत महिलाएं रक्ताल्पता से ग्रस्त हैं (रेखाचित्र 25)। भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत रक्ताल्पता की समस्या के समाधान के लिए स्वास्थ्य-पोषण शिक्षा, भोजन में विविधाता, लौह फोलिएट समृद्ध भोजन और लौह तत्व को शरीर में समाहित करने वाली खाद्य सामग्री को प्रचलित बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया है।

सरकार की समाहनकारी नीतियां

8.77 भारत सरकार का जीवन दर्शन है कि सीमांत, अभावग्रस्त और कमजोर वर्गों को एक उत्पादक, सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन सुलभ कराते हुए समाज के सभी वर्गों को संवृद्धि एवं विकास के समतापूर्ण अवसर सुलभ कराए जाएं। इसी ध्येय की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने सुगम्य भारत अभियान जैसे कार्यक्रमों का सूत्रपात किया है (बॉक्स-2)।

8.78 अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं चला रखी है। अल्पसंख्यक समाज की

रेखाचित्र 24 : प्रसव मृत्यु दर, राज्यानुसार (प्रति 100000 जीवित जन्म पर) 2011-13

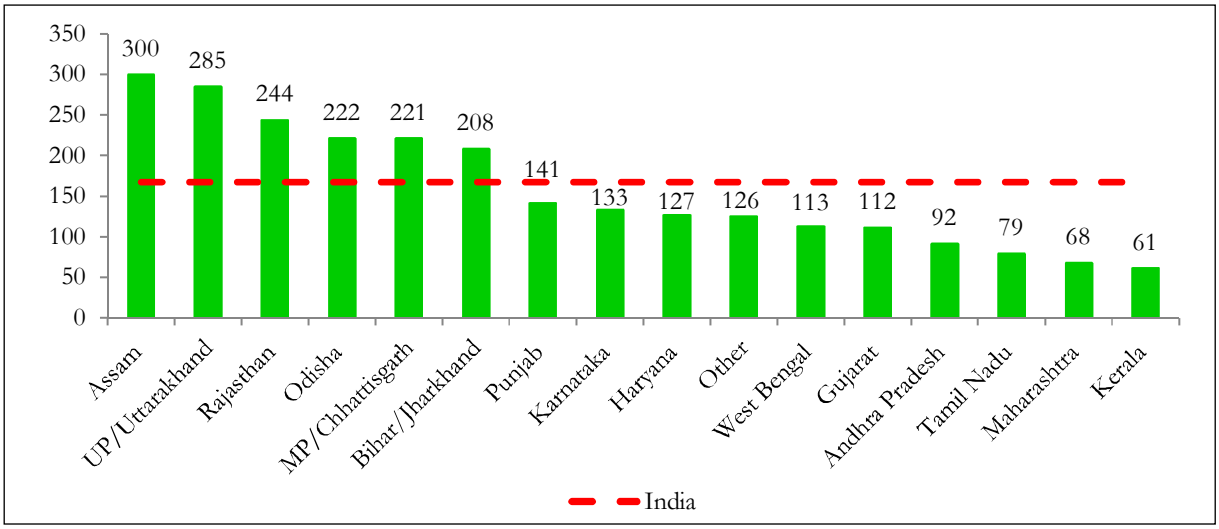

स्रोत: एमएमआर बुलेटिन 2011-13, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए नई रोशनी, अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर ब्याज में सब्सिडी के लिए 'पढ़ो परदेस' जैसी योजनाएं लागू की जा रही है। अल्पसंख्यकों के कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 'सीखो और कमाओ' 'परंपरागत कलाओं/हस्तकलाओं के विकास हेतु 'कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण' तथा 'नई मंजिल' योजनाएं अल्पसंख्यक युवाओं को शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण पदान करने के लिए चलाई जा रही हैं।

XIII. जलवायु (मौसम चक्र) परिवर्तन

अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन विचार विमर्श में उच्चावचन

8.79 दिसंबर 12, 2015 के दिन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन महासंधि रूपरेखा से जुड़े पक्षो (UNFCC) ने ऐतिहासिक पैरिस समझौते को स्वीकार किया। यह सभी राष्ट्रों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने और ऐसे कार्य एवं निवेश करने को एक जुट कर रहा है, जिनसे

रेखाचित्र 25 : विभिन्न राज्यों में रक्ताल्पतागग्रस्त पुरूष एवं स्त्रियों में प्रतिशत

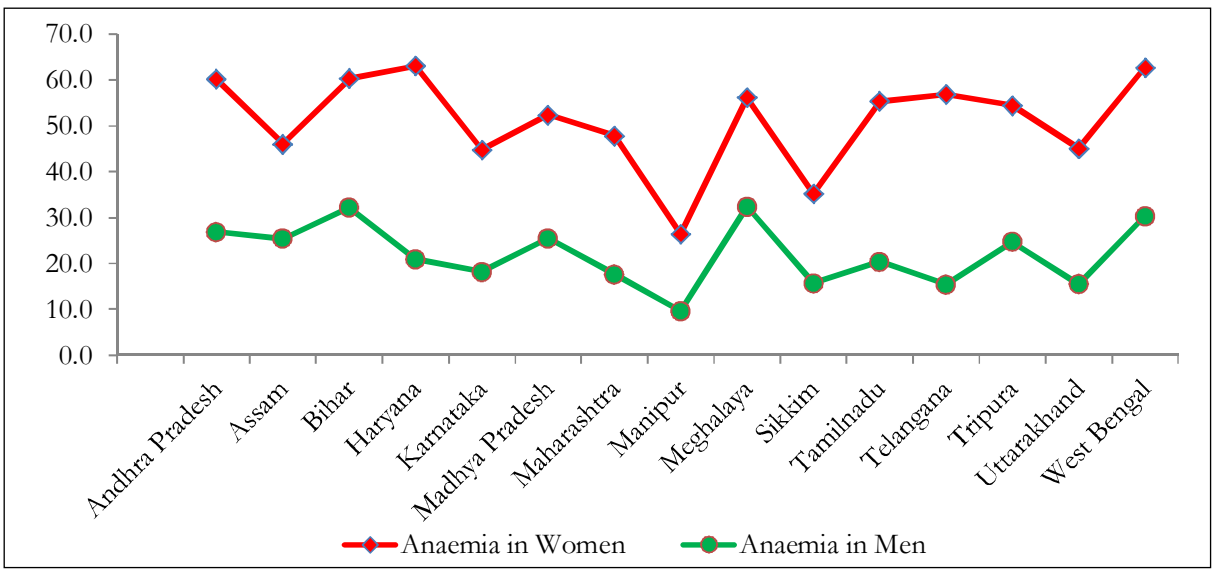

स्रोत : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-4) 2015-16, राज्यानुसार विवरण
नोट : यह महिलाओं के आंकड़ों में गर्भवती महिलाएं शामिल नहीं हैं।

बॉक्स 1 : प्रयोगात्मक स्वस्थता परिणाम सूचक

एक वर्ष की आयु पर जीवाशा (LE1) IMR और MMR सूचकों का प्रयोग कर एक प्रयोगात्मक स्वस्थता परिणाम सूचक (HO1) का आंकलन किया गया है। जहां 2010-14 के LE1, तथा अधिकांश प्रांतों के लिए IMR और MMR के आंकड़े 2011-13 की अवधि के हैं। अठारह राज्यों के लिए उपर्युक्त तीनों सूचकों के मानकीकरण से प्राप्त HO1 को रेखाचित्र B1 में अंकित किया गया है।

रेखाचित्र B1 : स्वस्थता परिणाम सूचक

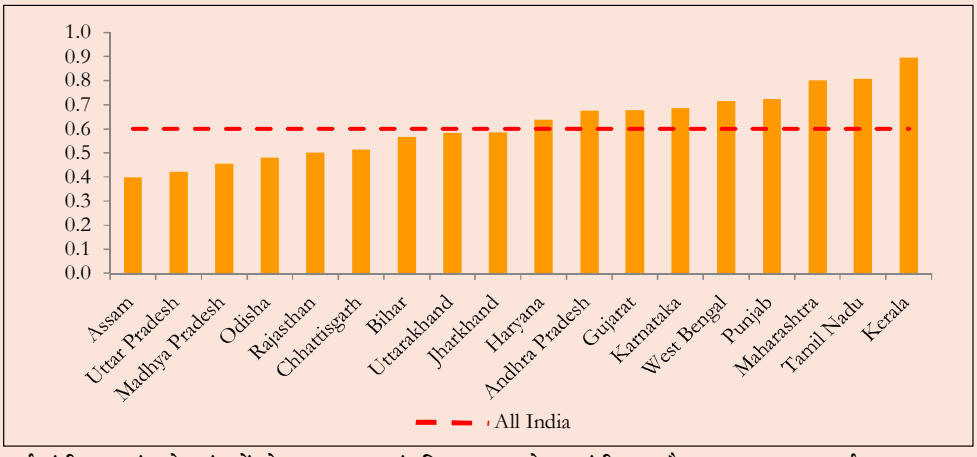

***स्रोत* : प्रतिदर्श पंजीकरण तंत्र के आंकड़ों के आधार पर आंकलित, भारत के महापंजीकार और जनगणना का कार्यालय**

नोट : मानकीकृत LE1 = (वास्तविक मान - न्यूनतम मान)/(अधिकतम मान - न्यूनतम मान)

मानकीकृत IMR = (अधिकतम मान - वास्तविक मान)/(अधिकतम मान - न्यूनतम मान)

मानकीकृत MMR = (अधिकतम मान - वास्तविक मान)/(अधिकतम मान - न्यूनतम मान)।

यहां अंकित आंध्र प्रदेश के आंकड़ों में तेलंगाना की जानकारी भी सम्मिलित है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार असम के स्वस्थता परिणाम न्यूनतम और केरल का सूचक उच्चतम है। अठारह में से 9 राज्यों के सूचक राष्ट्रीय औसत (0.6) से उच्च पाए गए हैं। न्यूनतम स्वस्थता सूचक वाले प्रदेश असम में MMR का स्तर उच्चतम है (देखें रेखाचित्र 24)।

निम्न कार्बन उत्सर्जक, सशक्त एवं धारणीय भविष्य का निर्माण हो सके। पैरिस समझौता 2020 के बाद से कार्य आधारित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDS) का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। यह पेरिस समझौता नवंबर 4, 2016 से लागू हो गया है।*

8.80 UNFCC से संबद्ध पक्षों का 22वां अधिवेशन सत्र (COP-22) मार्केश, मोरक्को में नवंबर 7-19, 2016 के बीच रहा। इस COP-22 का मुख्य आग्रह पेरिस समझौते को व्यवहारिक बनाने के लिए आवश्यक नियमों का विकास और व्यवहारिक कार्य योजना बनाना था ताकि 2020 से पहले करने योग्य कार्यों की दिशा में प्रगति हो सके। COP-22 में नियम निर्माण के लिए 2018 तक कार्य पूरा करने पर सहमति बनी है। विवरण में NDCs की लेखा पद्धति, स्वीकृति/अनुमोदन के संप्रेषण, पारदर्शिता प्रणाली का निर्माण और प्रत्येक पांचवे वर्ष वैश्विक समीक्षा आदि सम्मिलित हैं।

8.81 COP-22 का मुख्य निर्णय 'हमारे जलवायु एवं धारणीय विकास हेतु मार्केश कार्य उद्घोषणा' रहा। यह जलवायु परिवर्तन को लेकर तुरंत कुछ करने की चिंता को बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त करता है। मार्केश कार्य उद्घोषणा ने गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और कृषि की धारणीयता का संवर्धन करने के प्रयासों का समर्थन एवं उन्हें और सबल बनाने पर भी आग्रह किया है। वर्ष 2020 से पूर्व किए जाने वाले कार्यों में प्रतिवर्ष $100 बिलियन जुटाना इस उद्घोषणा का एक महत्वपूर्ण तत्व है।

* संयुक्त राज्य अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने अपने देश को इस समझौते से अलग कर लिया है।

बॉक्स 2 : सुगम्य भारत अभियान

एक समाज के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने सभी अपंगताग्रस्त सदस्यों के लिए समान मानवाधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं को भोग पाने को सुनिश्चित करने के आवश्यक उपाय करे 'ताकि वह वर्ग भी अपने अंतर्भूत सम्मान सहित जीवन यापन कर सके' (संयुक्त राष्ट्र अपंगताग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों पर महासंधि)। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की 2.2 प्रतिशत जनसंख्या ''दिव्यांग'' है। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग ने एक राष्ट्र व्यापि आंदोलन के रूप में सुगम्य भारत अभियान प्रारंभ किया है। इसका ध्येय दिव्यांग वर्ग के लिए सभी स्थानों को सुगम्य बनाना है। इस अभियान के तीन आग्रह ''उपयुक्त पर्याव्यवस्था की रचना, सार्वजनिक परिवहन और सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी'' के विकास पर है।

सरकार द्वारा प्रारंभ ''समाहन एवं सुगम्यता सूचक'', जो इस अभियान का एक अंग है, उद्योगों एवं निगमों को ऐच्छिक आधार पर अपने कार्यस्थलों की दिव्यांग वर्ग के लिए उपयुक्तता की समीक्षा करने को प्रोत्साहित करता है। यह सूचक देश की एक अनुपम पहल है और दिव्यांगों के मुख्य धारा से जुड़ने, समाहित होने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। यह सूचक विभिन्न निकायों/संस्थानों को अपनी दिव्यांग वर्ग नीतियों तथा संगठनात्मक संस्कृति, उन्हें रोजगार देने व उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने की तत्परता की आत्मालोचनपूर्ण समीक्षा करने योग्य बनाता है।

यही नहीं, ''दिव्यांग अधिकार विधेयक 2016'' को संसद ने पारित कर दिया है। यह भी उनके अधिकारों एवं अधिकारिताओं को सुनिश्चित एवं संवर्धित करने के विचार से प्रेरित है। विधोयक ने सरकारी निकायों/उपक्रमों में दिव्यांग जन आरक्षण को 3 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने का निर्णय किया है। यह लाभ सुनिश्चित दिव्यांगता और विशेष सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए होगा। इस विधेयक का विवरण यहां उपलब्ध है: http://pib.nic.in/nwwsite/PrintRelease.aspx?relied=155592

भारत के हरित प्रयास

8.82 भारत ने पेरिस समझौते का अक्टूबर 2, 2016 के दिन अनुमोदन कर दिया है। भारत का संपूर्ण NDC लक्ष्य GDP की उत्सर्जन गहनता को 2005 के 35 प्रतिशत से घटाकर 2030 तक 33 प्रतिशत करना है। साथ ही गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन को सकल स्थापित विद्युत क्षमता के 40 प्रतिशत तक ले जाना और अतिरिक्त संचयी 2.5 से 3 Gt CO_2e के समान कार्बन धारण क्षमता की रचना अतिरिक्त वृक्ष एवं वन रोपण द्वारा (2030 तक) करना है।

8.83 भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में इस समय बहुत बड़ा परिवर्तन चल रहा है और 2020 तक इस ऊर्जा सृजन की क्षमता 175 GW तक पहुँच जाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सौर-पार्क, सौर सुरक्षा योजना, केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए सौर योजना, नहर तटों और नहरों के ऊपर सौर फोटो वोल्टेक विद्युत संयंत्र, सौर पंप, सौर छत जैसे अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। पिछले ढाई वर्षों में ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक 14.3 GW क्षमता की स्थापना कर चुके हैं। इसमें से 5.8 GW सौर ऊर्जा 7.04 GW पवन ऊर्जा, 0.53 GW छाटी जल विद्युत योजनाओं और 9.93 जैव ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त हो रही है। उचित दिशा में उठाए गए सही कदमों के फलस्वरूप आज भारत विश्व का चौथे क्रम का पवन विद्युत क्षमता स्थापित करने वाला देश बन चुका है। इसका क्रम चीन, सं.रा. अमेरीका और जर्मनी के बाद आता है। अक्टूबर 31, 2016 तक भारत 46.3 GW ग्रिड संवेदी विद्युत क्षमता की स्थापना कर चुका था तो ग्रिड संबंधित क्षमता 7.5 GW थी। छोटे जल विद्युत संयंत्रों की क्षमता 4.3 GW थी। इनके साथ-साथ 92305 सौर पंप भी लगाए जा चुके थे। देश में रू. 38,000 करोड़ की लागत से एक 'हरित ऊर्जा पथ' की रचना की जा रही है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा को उत्पादन बिन्दु से प्रयोक्ताओं तक पहुँचाया जा सके।

8.84 जनवरी 2016 में सरकार ने राष्ट्रीय विद्युत शुल्क नीति में संशोधन किया है। ये संशोधन पर्यावरण पक्षों पर केंद्रित हैं। इनमें हैं : (1) मार्च 2022 तक जल विद्युत के अतिरिक्त विद्युत उपभोग में 8 प्रतिशत के समान बिजली अन्य नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त की जाएगी; (2) नवीकरणीय सृजन दायित्व के अंतर्गत नए कोयला/लिग्नाईट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को एक तिथि

के बाद नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता/खरीदारी/प्रापण भी करना होगा; (3) नवीकरणीय ऊर्जा का उन संयंत्रों से प्राप्त ऊर्जा के साथ संबंध बनाना होगा; जिनके साथ ऊर्जा खरीद अनुबंध अपनी व्यवहारिक आयु/अवधि पार कर चुके हैं; (4) सौर और पवन ऊर्जा पर कोई अंतर्राज्यीय संप्रेषण शुल्क नहीं लगेगा; (5) कचरे से सृजित सारी ऊर्जा की खरीद अनिवार्य होगी; (6) नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम के संवर्धान के लिए ग्रिड के कार्यों में सहायक सेवाएं प्रदान की जाएंगी, आदि।

8.85 भारत की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन (ISA) प्रारंभ हुआ है। यह सौर ऊर्जा समृद्ध देशों की ऊर्जा की विशेष जरूरतों को पूरा करने के ध्येय से त्रुटियों की पहचान कर एक सांझे कार्यक्रम के अनुसार कार्य को बढ़ावा देगा। अभी तक 24 देश इस IDS के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। यह हस्ताक्षर कार्य नवंबर 15, 2016 से ही प्रारंभ हुआ है। पंद्रह देशों के हस्ताक्षर के बाद ISA को संयुक्त राष्ट्र के अधिपत्र की धारा 102 के अंतर्गत पंजीकृत कराकर इसे एक अंतर्सरकार संधि का रूप दे दिया जाएगा। इसके विधायी पक्ष की रचना के बाद यह भारत में अवस्थित एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन जाएगा।

8.86 भारत ने जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलन कोष की स्थापना कर ली है। यह राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का जलवायु परिवर्तन के अनुकूल प्रकल्प कार्य योजनाएं लागू करने में सहायता प्रदान करेगा। अभी तक इस कोष से कृषि, पशुपालन, जल संसाधान, तटीय क्षेत्रों, जैव विविधता और परिस्थिति की सेवाओं से जुड़े प्रकल्पों के लिए रू. 182.3 करोड़ की राशियां प्रदान की जा चुकी हैं।

8.87 भारत कोयले पर कर लगाने वाले इनेगिने देशों में एक है। संघीय बजट 2016-17 में इस कोयला अधिभार का नाम ''स्वच्छ पर्यावरण अधिभार'' कर दिया गया है। यह राष्ट्रीय स्वच्छ पर्यावरण कोष के लिए धन जुटाता है। बजट 2016-17 में स्वच्छ पर्यावरण अधिभार की दर रू. 200 प्रतिटन से बढ़ाकर रू. 400 प्रति टन कर दी गई है। राष्ट्रीय स्वच्छ पर्यावरण कोष की राशियों का प्रयोग संप्रेषण क्षेत्रक, नमामि गंगे, हरित भारत मिशन, सौर सैल प्रकाश इकाइयों, छोटी प्रकाश इकाइयों, जल पंप हेतु SPV, और SPY आधारित विद्युत संयंत्रों तथा ग्रिड संबंधित छत पर लगे SPV विद्युत उत्पादन संयंत्रों के लिए किया जा रहा है।

परिशिष्ट

A1. भुगतान शेष का सार ($ BILLION)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2015-16	2016-17
		(अप्रैल-मार्च)			H1	H1
निर्यातए f.o.b	306.6	318.6	316.5	266.4	135.6	134.0
आयात, c.i.f	502.2	466.2	461.5	396.4	206.9	183.5
व्यापार शेष	-195.7	-147.6	-144.9	-130.1	-71.3	-49.5
सेवा निर्यात	145.7	151.8	158.1	154.3	77.0	80.1
सेवा आयात	80.8	78.7	81.6	84.6	41.4	48.0
सेवा निवल	64.9	73.1	76.5	69.7	35.6	32.0
आय (निवल)	-21.5	-23.0	-24.1	-24.4	-11.3	-14.1
निजी अंतरण (निवल)	64.3	65.5	66.3	63.1	32.7	28.2
अधिकारिक अंतरण (निवल)	-0.3	-0.2	-0.6	-0.5	-0.3	-0.4
अदृश्य (निवल)	107.5	115.2	118.1	107.9	56.7	45.7
चालू खाता शेष	-88.2	-32.4	-26.9	-22.2	-14.7	-3.7
पूंजी खाता बाह्य सहायता (निवल)						
व्यापारिक उधार (निवल)	1.0	1.0	1.7	1.5	0.2	0.5
विदेशी निवेश (निवल)	8.5	11.8	1.6	-4.5	-1.3	-4.6
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (निवल)	46.7	26.4	73.5	31.9	13.0	29.4
प्रवाह	19.8	21.6	31.3	36.0	16.5	21.3
अप-प्रवाह	39.8	43.6	51.8	59.9	26.8	38.3
पत्रक निवेश (निवल)	20.0	22.0	20.5	23.9	10.3	17.0
विदेशी संस्थागत निवेश (निवल)	26.9	4.8	42.2	-4.1	-3.5	8.2
गैर आवासी जमाएं (निवल)	27.6	5.0	40.9	-4.0	-3.8	7.9
रूपए ऋण सेवा	14.8	38.9	14.1	16.1	10.1	3.5
अन्य पूंजी प्रवाह (निवल)	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
अल्पकालिक साख (निवल)	21.0	-30.1	-2.5	-4.8	3.3	-9.5
बैंकिंग पूंजी (निवल)	21.7	-5.0	-0.1	-1.6	-2.5	-0.5
भूल-चूक	16.6	25.4	11.6	10.6	18.3	-6.8
अन्य (निवल)	2.7	-1.0	-1.0	-1.1	-1.5	-0.6
सकल पूंजी / वित्त खाता (निवल)	-19.9	-49.7	-13.0	-12.7	-11.0	-1.6
सुरक्षित परिवर्तन: (-) वृद्धि और (+) कमी	92.0	47.9	88.3	40.1	25.3	19.2
व्यापार शेष /GDP (प्रतिशत)	-3.8	-15.5	-61.4	-17.9	-10.6	-15.5
अदृश्य शेष /GDP (प्रतिशत)	-10.7	-7.9	-7.1	-6.3	-7.1	-4.6
चालू खाता /GDP (प्रतिशत)	5.9	6.2	5.8	5.2	5.7	4.3
निवल पूंजी प्रवाह/GDP (प्रतिशत)	-4.8	-1.7	-1.3	-1.1	-1.5	-0.3
शुद्ध पूंजी प्रवाह/जीडीपी (प्रतिशत)	5.0	2.6	4.3	1.9	2.5	1.8

स्रोत: **भारतीय रिज़र्व बैंक**

A2. चुनींदा खरीफ फसलों के अधीन क्षेत्रफल 14 अक्टुबर 2016

क्रम सं॰	फसलें	बुवाई क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)		पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
		2016-17	2015-16	2015-16
1.	चावल	391.24	381.09	2.66
2.	दालें	146.24	113.21	29.18
a.	अरहर	52.81	37.66	40.24
b.	उड़द	35.68	28.51	25.15
c.	मूंग	34.11	25.63	33.08
3.	मोटे अनाज	190.50	185.83	2.52
a.	जवार	19.59	19.88	-1.48
b.	बाजरा	70.43	70.50	-0.10
c.	रागी	10.40	11.69	-11.01
d.	खरीफ मक्का	84.43	77.91	8.37
4.	तेलीय बीज	190.31	185.19	2.77
a.	मूंगफली	47.07	36.79	27.95
b.	सोयाबीन	114.78	116.29	-1.29
c.	सूरजमुखी	1.69	1.50	12.41
5.	गन्ना	46.13	49.61	-7.01
6.	पटसन और मेस्टा	7.59	7.73	-1.86
7.	कपास	103.69	117.09	-11.44
	योग	**1075.71**	**1039.74**	**3.46**

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

A3: दाल उत्पादन को संप्रेरित करना : सिफारिशों की संक्षिप्त सूची

	नीति	समय सीमा
I.	**न्यूनतम समर्थनकीमत और प्रापण**	
(क)	सरकारी प्रापण तन्त्र को पूरी तरह तैयार होकर इस मौसम में घोषित MSP पर खरीफ की 29 दालों की खरीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।	तुरन्त
(ख)	प्रभावी प्रापण के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन हो, जिसमें वित्त, कृषि और उपभोक्ता मामलों के मंत्री और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव शामिल हों। क्षेत्र में कार्य कर रही एजेंसियां साप्ताहिक आधार पर इस समिति को रिपोर्ट देंगी। प्रापण के वास्तविक भंडारों का सत्यापन भी होना चाहिए।	तुरंत
(ग)	दालों के 2 मिलियन टन का भंडार बनाया जाए, जिसमें अरहर का 3.5 लाख टन और उड़द का 2 लाख टन का लक्ष्य हो। ये भंडार धीरे-धीरे, जब कम दाम पर खरीदारी का अवसर मिले, बनाना चाहिए।	तुरंत
(घ)	अल्पकाल में तैयार होने वाले अरहर को बाजार में लाते समय खरीफ 2018 में MSP को रू. 70 प्रतिकिलो ग्राम तक पहुँचाना। किसानों को सिंचाई वाले क्षेत्रों में 10-15 रूपए किलोग्राम सब्सिडी सीधे लाभ अन्तरण द्वारा करने के प्रयास किए जाएं।	प्रारंभिक सुझाव 2018 की खरीफ से। किन्तु यह शीघ्र शुरू होने वाला है।
(च)	कृषि लागत एवं कीमत आयोग को अपनी MSP निर्धारण व्यवस्था की रूपरेखा की समीक्षा करते हुए इस रिपोर्ट में बताई गई जोखिम और सामाजिक बाह्यताओं को शामिल करने का निर्देश दिया जाए।	तुरंत
II.	**अन्य कीमत प्रबंधन नीतियां**	
(क)	दालों पर भंडार सीमाएं और निर्यात प्रतिबंध तुरंत निरस्त किए जाएं (कम से कम थोक विक्रेताओं पर कोई स्टॉक सीमा लागू नहीं हो। सरकार की भंडार सीमा जितनी अधिक होगी, उतनी गंभीरता से प्रापण कार्य कर (MSP से ऊपर) बाजार कीमतों को स्थायी बनाने का कार्य होगा। किसान के लिए सबसे पीड़ादायक वह स्थिति होती है, जब प्रापण तंत्र कमजोर हो और उसे स्टॉक सीमाओं के कारण अपना ज्यादा से ज्यादा माल MSP से बहुत कम दामों पर बेचने को विवश होना पड़ रहा हो। अधिक व्यापक रूप में आन्तरिक कीमतों पर नियंत्रण के लिए विदेश व्यापार नीति का प्रयोग उचित नहीं है। यह नीतिगत स्तर पर अस्थिरता पैदा कर सकती है।	तुरंत
(ख)	राज्य सरकारों को प्रोत्साहन दिया जाए कि वह दालों को कृषि उपज विपणन समितियों से मुक्त कर दें	तुरंत
(ग)	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और कृषि उपजों के वायदा बाजार की समीक्षा हो, इसमें मूल उद्देश्यों को बनाए रखते हुए उन्हें प्राप्त करने के अधिक प्रभावी और कम खर्चीले उपाय तलाश किए जाने चाहिए।	जब उचित पाया जाए
III.	**प्रापण-भंडारण-संभरण संस्थाएं**	
(क)	सार्वजनिक निजी भागीदारी में एक नई संस्था का गठन हो जो प्रापण और दालों के संभरण में अभी काम कर रही संस्थाओं से स्पर्धापूर्वक कार्य करें।	इस पर तुरंत कार्य प्रारंभ हो ताकि रबी 2016 तक यह पूरी तरह से काम करने लगे। केबिनेट के विचार के लिए उपयुक्त प्रस्ताव 4 सप्ताह में तैयार किया जाए
(ख)	भंडारों से संभरण के स्पष्ट नियम बनाए जाएं	
IV.	**विपरीत प्रभावों को न्यूनतम किया जाए**	
(क)	जैविक परिवर्तन वाली प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जाए। दालों की स्वदेश विकसित किस्मों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए।	आवश्यकतानुसार

A4. प्रमुख उपजों की न्यूनतम समर्थन कीमतें (रूपए प्रति क्विंटल)

वस्तु समूह	2015-16	2016-17
खरीफ फसलें		
धान-साधारण	1410	1470
धान (A ग्रेड)	1450	1510
जवार (संकर)	1570	1625
जवार (मालडंडी)	1590	1650
बाजरा	1275	1330
रागी	1650	1725
मक्का	1325	1365
अरहर	4625^	5050*
मूंग	4850^	5225*
उड़द	4625^	5000*
मूंगफली	4030	4220$
सूरजमुखी बीज	3800	3950$
सोयाबीन (पीली)	2600	2775$
तिल	4700	5000#
राम तिल्ली	3650	3825$
कपास (मध्यम रेशा)	3800	3860
कपास (लम्बा रेशा)	4100	4160
रबी फसलें		
गेहूँ	1525	1625
जौ	1225	1325
चना	3425^^	4000**
मसूर	3325^^	3950##
तोरिया/सरसों	3350	3700**

स्रोत : कृषिक लागत और कीमत आयोग

नोट : *कोष्ठक प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं। ^ : रू. 200 प्रति क्विंटल का बोनस शामिल है, *: रू. 425 प्रति क्विंटल बोनस सहितए $: रू. 100 प्रति क्विंटल बोनस सहितए # : रू. 200 प्रति क्विंटल बोनस सहितए ^^ : रू. 75 प्रति क्विंटल बोनस सहितए ** : रू. 200 प्रति क्विंटल बोनस सहितए ## : रू. 100 प्रति क्विंटल बोनस सहित*